3.4.5 / 15 PKM

ISSN : 0975-6825

INDIAN JOURNAL OF BUSINESS ADMINISTRATION (IJBA)

Department of Business Administration, Faculty of Commerce and Management Studies
Jaswant Campus, Jai Narain Vyas University, Jodhpur
www.busadmjnvu.org

Dated :30-06-2021

Certificate of Publication

IJBA is delighted to award you for publishing your Article/Research paper entitled

ISSUES AND CHALLENGES OF CORPORATE GOVERNANCE

Authored by

Dr. Pushpendra Kumar Musha

Assistant Professor, Faculty of Law, Jai Narain Vyas University, Jodhpur, Rajasthan (India)

Published in Volume 14, Issue 01, Jan–Jun, 2021 of Indian Journal of Business Administration (IJBA), Peer Reviewed Refereed Journal.

We congratulate you for the successful publication.

Dean & Head
Faculty of Law
J.N.Vyas University
Jodhpur

Dr. Ashok Kumar
Managing Editor

Dr. Umaid Raj Tater
Chief Editor

Dean & Head
Faculty of Law
Vyas University
Jodhpur

3.4.5/3
SPM

Dean & Head
Faculty of Law
J.N.Vyas University
Jodhpur

ISSN : 0976-0024

अप्रैल-जून 20

अंक : 1

महिला
Mahila

विधि भारती
Vidhi Bharati

विधि चेतना की द्विभाषिक (हिन्दी-अंग्रेजी) शोध पत्रिका
Research (Hindi-English) Quarterly Law Journal

- भारत का संविधान और मौलिक कर्त्तव्य
- भारत में लैंगिक असमानता : वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, 2020
- हिंदी के अच्छे दिन : एक रिपोर्ट
- भारतीय न्यायालयों एवं कारावासों पर अतिभार
- भारत में गरीबी उन्मूलन : सामाजिक कानूनी पहलू
- प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम पर इंटरनेट पायरेसी के प्रभाव और कोविड-19
- उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा की चुनौती
- भारतीय संविधान में आरक्षण व बाबा साहब अंबेडकर
- कोविड-19 संकट और प्रवासी मजदूरों की समस्याएँ
- घरेलू हिंसा के आयाम और कोविड-19
- विधि, न्याय तथा न्यायिक प्रक्रिया
- कोरोना महामारी : भारत में विधिक विनियमन
- 'काव्य मंथन' संगोष्ठी : विधि भारती परिषद्
- A Cursory Study of Liability of Internet Service Providers Under I.T. Act, 2000
- The Union and The State Relationship
- Constitutionality of Delegated Legislation in India
- Juvenile Justice System in India

Editor-in-Chief : Santosh Khanna

[1][भारत का संविधान, अनुच्छेद 51-ए

नागरिकों के मूल कर्तव्य

51क. मूल कर्तव्य : भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह --

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे;

(ख) स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सँजोए रखे और उनका पालन करे;

(ग) भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे;

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे;

(ङ) भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है;

(च) हमारी सामासिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे;

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणि मात्र के प्रति दया भाव रखे;

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे;

(झ) सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे;

(ञ) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू ले;]

[2][(ट) यदि माता-पिता या संरक्षक है, छह वर्ष से चौदह वर्ष तक की आयु वाले अपने, यथास्थिति, बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करे ।]

1. संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 11 द्वारा (3-1-1977 से) अंतःस्थापित ।
2. संविधान (छियालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, की धारा 4 द्वारा (अधिसूचना की तारीख से) अंतःस्थापित किया जाएगा ।

Dean & Head
Faculty of Law
J.N. Vyas University
Jodhpur

अप्रैल-जून अंक : 103 2020
April-June ISSN : 0976-0024

महिला Mahila
विधि भारती
Vidhi Bharati

विधि चेतना की द्विभाषिक (हिंदी-अंग्रेज़ी) शोध पत्रिका
Research (Hindi-English) Quarterly Law Journal

(केंद्रीय हिंदी निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आंशिक अनुदान से प्रकाशित)

ISSN 0976-0024

प्रधान संपादक
सन्तोष खन्ना
संपादक
डॉ. उषा देव

पत्रिका में व्यक्त विचारों से सम्पादक/परिषद् की सहमति आवश्यक नहीं है।
Indexed at Indian Documentation Service, Gurugram, India
Citation No. MVB-25-26/2020

विधि भारती परिषद्
बी.एच./48 (पूर्वी) शालीमार बाग, दिल्ली-110088 (भारत)
मोबाइल : 09899651872, 09899651272
फोन : 011-27491549, 011-45579335
E-mail : vidhibharatiparishad@hotmail. com, santoshkhanna25@gmail. com
Website : www. vidhibharatiparishad.in

'महिला विधि भारती' पत्रिका (पूर्व यू.जी.सी. की सूची में भी शामिल, क्रमांक 156, पत्रिका संख्या 48462)

विधि चेतना की द्विभाषिक (हिंदी-अंग्रेज़ी) विधि-शोध त्रैमासिक पत्रिका

E-mail : vidhibharatiparishad@hotmail. com

Website : www. vidhibharatiparishad. in

अंक : 103 (अप्रैल-जून, 2020)

प्रधान संपादक : सन्तोष खन्ना, **संपादक :** डॉ. उषा देव

बोर्ड ऑफ रेफरीज एवं परामर्श मंडल

1. डॉ. के.पी.एस. महलवार : चेयर प्रो., प्रोफेशनल एथिक्स, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, न.दि.
2. डॉ. चंदन बाला : डीन एवं विभागाध्यक्ष, विधि विभाग, जयनारायण व्यास वि.वि., जोधपुर
3. डॉ. राकेश कुमार सिंह : पूर्व डीन एवं विभागाध्यक्ष, फैकल्टी ऑफ लॉ, लखनऊ विश्वविद्यालय
4. डॉ. किरण गुप्ता : पूर्व डीन एवं विभागाध्यक्ष, फैकल्टी ऑफ लॉ, दिल्ली विश्वविद्यालय
5. न्यायमूर्ति श्री एस.एन. कपूर : पूर्व न्यायाधीश, दिल्ली उच्च न्यायालय, पूर्व सदस्य, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग, नई दिल्ली।
6. प्रो. (डॉ.) सिद्धनाथ सिंह : पूर्व डीन एवं विभागाध्यक्ष, विधि विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय
7. प्रो. (डॉ.) गुरजीत सिंह : संस्थापक वाइस चांसलर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एवं न्यायिक अकादमी, असम
8. श्री हरनाम दास टक्कर : पूर्व निदेशक, लोक सभा सचिवालय, नई दिल्ली

परिषद् की कार्यकारिणी, संरक्षक : डॉ. राजीव खन्ना

1. डॉ. सुभाष कश्यप (अध्यक्ष)
2. न्यायमूर्ति श्री लोकेश्वर प्रसाद (उपाध्यक्ष)
3. श्रीमती सन्तोष खन्ना (महासचिव)
4. रेनू नूर (कोषाध्यक्ष)
5. श्री अनिल गोयल (सचिव, प्रचार)
6. डॉ. प्रवेश सक्सेना (सदस्य)
7. डॉ. आशु खन्ना (सदस्य)
8. डॉ. पूरनचंद टंडन (सदस्य)
9. श्री जी.आर. गुप्ता (सदस्य)
10. डॉ. उषा टंडन (सदस्य)
11. डॉ. सूरत सिंह (सदस्य)
12. डॉ. के.एस. भाटी (सदस्य)
13. डॉ. शकुंतला कालरा (सदस्य)
14. डॉ. एच. बालसुब्रह्मण्यम् (सदस्य)
15. डॉ. उमाकांत खुबालकर (सदस्य)
16. अनुरागेंद्र निगम (सदस्य)

शुल्क दर

वार्षिक शुल्क 500/-- रुपए
संस्थागत वार्षिक शुल्क 500/-- रुपए
आजीवन शुल्क 5,000/-- रुपए
संस्थागत आजीवन शुल्क 20,000/-- रुपए

डाक शुल्क अलग

Dean & Head
Faculty of Law
J.N.Vyas University
Jodhpur

अंक 103 में

1. संपादकीय -- 10
2. भारत का संविधान और मौलिक कर्त्तव्य / **हर्ष वनसोडे एवं कर्ण बगोरा** -- 11
3. भारत में लैंगिक असमानता : वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, 2020 / **डॉ. फरहत खान** -- 11
4. हिंदी के अच्छे दिन : एक रिपोर्ट / **सन्तोष खन्ना** -- 12
5. भारतीय न्यायालयों एवं कारावासों पर अतिभार / **डॉ. जयश्री नंदेश्वर** -- 12
6. भारत में गरीबी उन्मूलन : सामाजिक क़ानूनी पहलू / **प्रो. जयप्रकाश आर्य** -- 12
7. प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम पर इंटरनेट पायरेसी के प्रभाव और कोविड-19 / **श्रीमती नीतिनिपुण सक्सेना** -- 13
8. उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा की चुनौती / **डॉ. मंजू चंद्रा** -- 13
9. भारतीय संविधान में आरक्षण व बाबा साहब अंबेडकर / **संतोष बंसल रिपोर्ट** -- 14
10. कोविड-19 संकट और प्रवासी मजदूरों की समस्याएँ / **डॉ. निशा केवलिया शर्मा** -- 14
11. घरेलू हिंसा के आयाम और कोविड-19 / **डॉ. सुनीता श्रीवास्तव** -- 15
12. विधि, न्याय तथा न्यायिक प्रक्रिया / **सत्यम चंसोरिया** -- 15
13. कोरोना महामारी : भारत में विधिक विनियमन / **डॉ. शीतल प्रसाद मीना** -- 16
14. 'काव्य मंथन' संगोष्ठी : विधि भारती परिषद् / **अरविंद भारत** -- 16
15. A Cursory Study of Liability of Internet Service Providers Under I.T. Act, 2000 / **Poonam Pant and Bhumika Sharma** -- 17
16. The Union and The State Relationship – An Elementary Knowledge abou the role of their working and functions including the current Fiscal Scenaric of National Unity / **Shivangi Pawar** -- 18
17. Constitutionality of Delegated Legislation in India / **Prerna Pandey** -- 18
18. Juvenile Justice System in India / **Richa Shrivastava** -- 19

IMS UNISON UNIVERSITY
Nurturing Knowledge. Empowering Minds.

ISSN 2278-8093

Pragyaan

Volume 10, Issue 1, June 2020

Pragyaan: Journal of Law
a bi-annual refereed Journal

3.4.5/4
SPM

Research Papers

Cession of Erstwhile French Colony Chandernagore to India: Legal and Constitutional Issues
Dr. L.S. Nigam

Teaching Pedagogy Vis- a-Vis Evaluation Techniques
Dr. Anand Kumar Tripathi

Anti-Defection Law: A need for Reconsideration
Prof. (Dr.) R. N. Sharma

The Imperative of Medical Evidence in Personal Injury Litigation: Nigeria in Focus
Dr. Dennis Odigie

Paradigm Shift in Indian Legislature with Reference to Criminal Responsibility of an Unsound Mind
Mahesh A Tripathi, Anand Kumar Tripathi

Paralysing The Constitution of India by Religious Fundamentalists: A Tragedy
Dr. Nitesh Saraswat

Constitutionality of Ordinance 2020 to Amend Epidemic Diseases Act to Encounter Covid – 19
Dr. Madhu Soodan Rajpurohit

A Study in the Context of Indian Constitutional Provisions: Social & Sexual Discrimination
Dr. Surender Singh

Social Security for the Disabled Workers in Industrial Establishments: Legal Issues
Dr. Sheetal Prasad Meena

The Epidemic Disease Act,1897: A Tool to Control Covid -19
Dr. Anila

The DNA Technology (Use & Application) Regulation Bill, 2019 Vis-a-Vis Data Privacy
Arnav Bishnoi

The Rohingya's Crisis: Accusation of Genocide, The International Conventions & Indian Response
Saif Rasul Khan

Internet Access as a Human Right in the Age of Information: Anatomy of Virtual Curfew
Dr. Priyanka Anand

Legal Initiatives in India Towards Protection of Migrant Labours in Covid-19 Pandemic
Dr. R.Seyon

Victim Blaming: Transgression from the Real World to the Virtual World
Sakshee Sharma

Significance of Equity in Globalized World
Maryanka

Womanhood vis-a-vis the Right to Termination of Pregnancy: A Constitutional Framework
Pallavi Bajpai, Ruchika Sharma

How Effective is the Insolvency and Bankruptcy Code 2016?
Siddharth Dubey

Book Review

World Trade Law: Text, Materials and Commentary (Third Edition), Simon Lester, Bryan Mercurio & Arwel Davies
Dr. Rinu Saraswat

Introduction to the Constitution of India (24th Edition) by D.D Basu published by Lexis Nexis, Chennai
Mr. Nikunj Singh Yadav

"LEGAL WRITING STYLE" Third Edition 2018 , Author Antonio Gidi Teaching Professor of Law Syracuse University College of Law and Henry Weihofen Late Professor of Law University of New Mexico School of Law, Hornbook Series,
Prof. (Dr.) R. N. Sharma

Case Comment

Public Interest Foundation v Union of India, (2019) 3 SCC 224
Ms. Shalini Saxena

S. Teja Singh vs Satya and Ors.,1971 CrLJ 399
Anand Singh

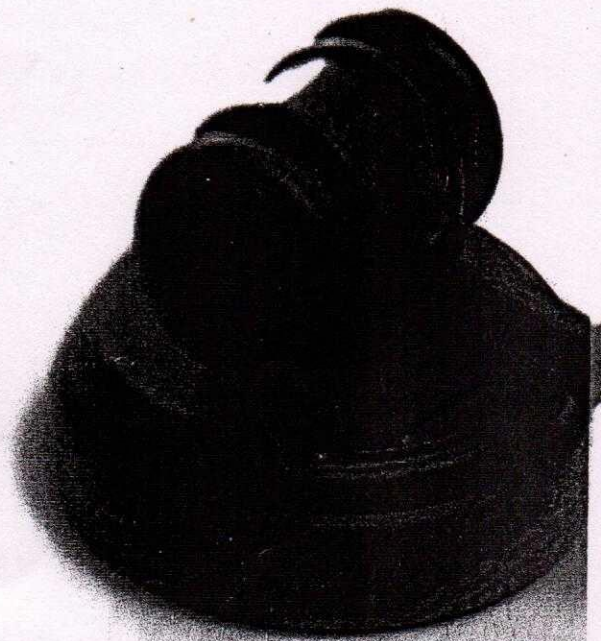

Dean & Head

Pragyaan: Journal of Law

Patron: **Prof. Gautam Sinha**
Vice Chancellor,
IMS Unison University, Dehradun

Editor: **Prof. (Dr.) R.N. Sharma**
Dean- School of Law,
IMS Unison University, Dehradun

Editor: **Dr. Shoaib Mohammad**
Assistant Professor,
IMS Unison University, Dehradun

Editorial Board Members:

Mr. Nikunj Singh
Assistant Professor,
IMSUnison University, Dehradun

Ms. Arnisha Ashraf
Assistant Professor,
IMSUnison University, Dehradun

Ms. Garima Trivedi
Assistant Professor,
IMSUnison University, Dehradun

Ms. Maryanka
Assistant Professor,
IMSUnison University, Dehradun

International Advisory Board:

Prof. Janine S. Hiller
Professor of Business Law,
Pamplin College of Business, Virginia, U.S.A.

Prof. Yousuf Dadoo,
University of South Africa,
Pretoria, South Africa

Prof. Arnaldo Sobrinho de Morais Neto
Lt. Col. Brazilina Military Police,
Professor IESP/Fesp College, Brazil

Prof. Fiona de Londras
Chair of Global Legal Studies,
University of Brimingham, U.K.

National Advisory Board:

Prof. B. L. Sharma
Vice-Chancellor, Pandit Deendayal Upadhayaya Shekhawati University, Rajasthan

Prof. Ashwani Kumar Bansal
Vice Chancellor, Maharaja Suraj Mal Brij University, Rajasthan

Prof. Subir K Bhatnagar
Vice Chancellor, RM LNLU, Lucknow

Prof. Amarendra N. Misra
Vice Chancellor, Khallikote Cluster University, Odisha

Prof. Subash Chander Raina
Former Vice Chancellor, HPNLU, Himachal Pradesh, Director KIIT School of Law, Orissa

Prof. (Dr.) Chidananda Reddy S. Patil
Dean & Director, Karnataka State Law University, Karnataka

Prof. Paramjit S. Jaswal
Vice Chancellor,
Rajeev Gandhi National Law University, Punjab

Prof. R. Venkata Rao
Chairperson, Vivekananda School of Law & Legal Studies & Vivekananda School of School of English Studies, Delhi, Former Vice Chancellor, NLSIU, Bengaluru

Prof. B. C. Nirmal
Former Vice Chancellor, Nation University of Study and Research in Law, Ranchi

Prof. Naresh Dadhich
Former Vice Chancellor, Vardhaman Mahaveer Open University, Rajasthan

Prof. Bhavani Prasad Panda
Former Vice Chancellor,
Maharashtra National Law University, Mumbai

Prof. V. K. Ahuja
Professor-In-Charge,Law Centre-II, Delhi University

Copyright 2020 © IMS Unison University, Dehradun.

No part of this publication may be reproduced or transmitted in only form or by any means, or stored in any retrieval system of any nature without prior permission. Application for permission for other use of copyright material including permission to reproduce extracts in other published works shall be made to publishers. Full acknowledgement of author, publishers and source must be given.

The Editorial Board invites original, unpublished contributions in the form of articles, case studies, research papers, book reviews.

The views expressed in the articles are those of the contributors and not necessarily of the Editorial Board or the Institute.

Although every care has been taken to avoid errors or omissions, this publication is being sold on the condition and understanding that information given in this journal is merely for reference and must not be taken as having authority of or binding in any way on the authors, editors, publishers and sellers who do not owe any responsibility for any damage or loss to any person, a purchaser of this publication or not, for the result of any action taken on the basis of this work. All disputes are subject to Dehradun jurisdiction only.

Dean & Head
Faculty of Law

Pragyaan: Journal of Law

Volume 10, Issue 1, June 2020

CONTENTS

ISSN 2278-8093

1. Cession of Erstwhile French Colony Chandernagore to India: Legal and Constitutional Issues — 1-6
   Dr. L.S. Nigam
2. Teaching Pedagogy Vis- a-Vis Evaluation Techniques — 7-10
   Dr. Anand Kumar Tripathi
3. Anti-Defection Law: A need for Reconsideration — 11-21
   Prof. (Dr.) R. N. Sharma
4. The Imperative of Medical Evidence in Personal Injury Litigation: Nigeria in Focus — 22-28
   Dr. Dennis Odigie
5. Paradigm Shift in Indian Legislature with Reference to Criminal Responsibility of an Unsound Mind — 29-34
   Mahesh A Tripathi, Anand Kumar Tripathi
6. Paralysing The Constitution of India by Religious Fundamentalists: A Tragedy — 35-38
   Dr. Nitesh Saraswat
7. Constitutionality of Ordinance 2020 to Amend Epidemic Diseases Act to Encounter Covid – 19 — 39-50
   Dr. Madhu Soodan Rajpurohit
8. A Study in the Context of Indian Constitutional Provisions: Social & Sexual Discrimination — 51-56
   Dr. Surender Singh
9. Social Security for the Disabled Workers in Industrial Establishments: Legal Issues — 57-61
   Dr. Sheetal Prasad Meena
10. The Epidemic Disease Act,1897: A Tool to Control Covid -19 — 62-67
    Dr. Anila
11. The DNA Technology (Use & Application) Regulation Bill, 2019 Vis-a-Vis Data Privacy — 68-78
    Arnav Bishnoi
12. The Rohingya's Crisis: Accusation of Genocide, The International Conventions & Indian Response — 79-86
    Saif Rasul Khan
13. Internet Access as a Human Right in the Age of Information: Anatomy of Virtual Curfew — 87- 92
    Dr. Priyanka Anand
14. Legal Initiatives in India Towards Protection of Migrant Labours in Covid-19 Pandemic — 93-100
    Dr. R.Seyon
15. Victim Blaming: Transgression from the Real World to the Virtual World — 101-104
    Sakshee Sharma
16. Significance of Equity in Globalized World — 105-109
    Maryanka
17. Womanhood vis-a-vis the Right to Termination of Pregnancy: A Constitutional Framework — 110-115
    Pallavi Bajpai, Ruchika Sharma
18. How Effective is the Insolvency and Bankruptcy Code 2016? — 116-122
    Siddharth Dubey

Dean & Head

Book Review

19. World Trade Law: Text, Materials and Commentary (Third Edition), Simon Lester, Bryan Mercurio & Arwel Davies 123
Dr. Rinu Saraswat

20. Introduction to the Constitution of India (24th Edition) by D.D Basu published by Lexis Nexis, Chennai 124-125
Mr. Nikunj Singh Yadav

21. "LEGAL WRITING STYLE" Third Edition, 2018, Author Antonio Gidi Teaching Professor of Law Syracuse University College of Law and Henry Weihofen Late Professor of Law University of New Mexico School of Law, Hornbook Series, 126-127
Prof. (Dr.) R. N. Sharma

Case Comment

22. Public Interest Foundation v Union of India, (2019) 3 SCC224
Ms. Shalini Saxena 128-129

23 S. Teja Singh vs Satya and Ors.,1971 CrLJ 399
Anand Singh 130-131

Dean & Head
Faculty of Law
J.N.Vyas University
Jodhpur

Social Security for the Disabled Workers in Industrial Establishments: Legal Issues

Dr. Sheetal Prasad Meena*

Introduction

Human needs social security in the society. Disabled persons are also part of our society. Due to industrial development every person of society affected. Disability is neither a physical problem nor a health problem. It is the result of negative interactions that take place between a person with impairment and her or his social environment. There are many Acts which have been enacted by the government for the benefit of the disabled or the physical and mentally challenged. Still they seems ineffective to disabled persons. Society cannot be changed by merely by making laws there needs a enforcement mechanism. These persons are deprived of Right to employment , Right to work & livelihood, Right to social security , Right to life with dignity etc.

A first step toward a consistent explanation of the prior work requirement is to note its relation to the insurance aspect of Social Security. The requirement ensures that the claimant has paid the Social Security tax for a significant period. Thus benefits can be characterized not as public charity but as a return of insurance proceeds to the disability claimant who has paid tax "premiums" to purchase protection against the risk of disability. The insurance concept is not an entirely satisfactory explanation for the prior work requirement, however, for it could as easily justify coverage for all those now excluded by the requirement.

We could assume that all persons undertake to pay insurance premiums if and when they work, and that the promise to pay these premiums is consideration for an insurance contract by which society agrees to protect against the possibility that an individual will become disabled after working and paying taxes, or be disabled throughout his life and so never achieve a status of taxpaying productivity. That this societal insurance concept has not been adopted indicates that we may be unwilling to regard as insurance a scheme that does not require a connection between an individual's actual contributions and the benefits he will receive.[1]

Definition of Social Security:

The definition of social security includes Social insurance, Social Assistance, Family Benefits, Health Care and other Social services, related social welfare services etc. Right to an adequate standard of living for the health and well being of himself and his family, clothing, including food, and housing and medical care and sickness, disability, widowhood, old age and necessary social security in the event of unemployment or other lack of livelihood in circumstances beyond his control, is provided to every individual. At all times and in every society, at every stage of development, there have been sick people requiring medical aid and care, handicapped and old people are unable to work for a living.[2]

According to a definition given in the ILO publication- Approaches to Social Security (1949), *"Social security is the security that society furnishes through appropriate organization against creation risks to which its members are exposed. These risks are essentially contingencies of life which the individual of small means alone cannot effectively provide by his own ability or foresight or even in private combination with his fellows"*.

United Nations Organizations and Disabled persons :

According to Universal Declaration of Human Rights, 1948, *"All human being are born free and equal in dignity and rights"*. Nevertheless, this is far from being a reality for more than 500 million disabled persons around the world. Disabled persons living conditions are worse than those of other citizens. They are very often isolated and socially marginalized. They face discrimination virtually in all aspects of life. To combat this situation, specific rights have been evolved to protect disabled persons.

According to definition contained in the Declaration of the Rights of Disabled Persons (1975), the term 'Disabled Persons' *"any person unable to ensure by himself or herself, wholly or partly, the necessities of a normal individual and/or social life, as a result of a deficiency, either*

*Associate Professor, Govt. PG. Law College, Pali

1 The definition of disability in social security and supplemental security income: drawing the bounds of social welfare estates, Lance Liebman, Harvard law review, Volume 89, No. 5, Columbia Law School, March 1976.

2 Srivastav, Suresh C., Treatise on Social Security and labour Law, Lucknow Eastern Book Company, 1985, P.1.

Dean & Head
Faculty of Law
J.N.Vyas University

GOVT. OF INDIA- RNI NO. UPBIL/2014/56766
UGC Approved Care Listed Journal
ISSN 2348-2397

शोध सरिता

An International Multidisciplinary Quarterly
Bilingual Peer Reviewed Refereed Research Journal

• Vol. 7 • Issue 25 • January to March 2020

3.4.5/6
SPM

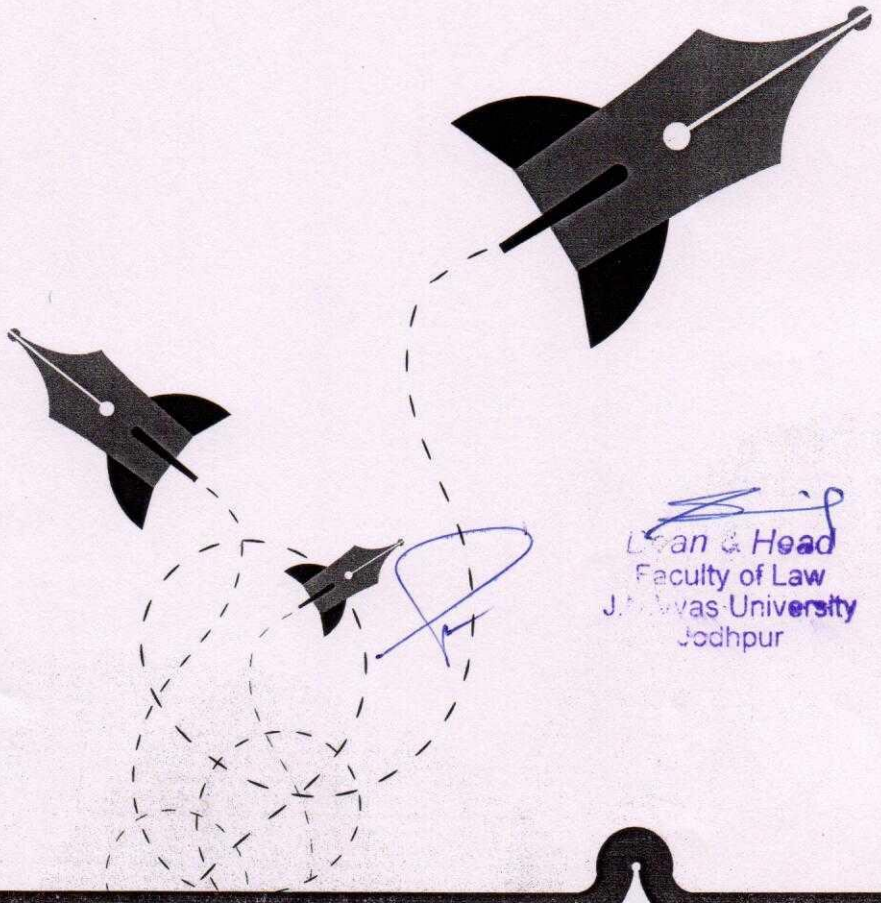

Dean & Head
Faculty of Law
J.N.Vyas University
Jodhpur

Editor in Chief
Dr. Vinay Kumar Sharma
D. Litt. - Gold Medalist

sanchar
Educational & Research Foundation

ISSN - 2348-2397
APPROVED UGC CARE

SHODH SARITA

SHODH SARITA
Vol. 7, Issue 25, January-March, 2020
Page Nos. 34-36

AN INTERNATIONAL BILINGUAL PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

भारत में ऑनर किलिंग : एक चुनौती

❐ डॉ0 शीतल प्रसाद मीना*

शोध सारांश

वर्तमान समय में भारत सहित विश्व के कई देशों में सम्मान के नाम पर दो वयस्कों द्वारा एक ही गोत्र परिवार, समाज या धर्म में विवाह करने पर हत्या करने की घटनाएँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इससे व्यक्ति के जीने के अधिकार से वंचित हो जाता है तथा संवैधानिक तथा विधिक अधिकारों का हनन भी होता है। इस संबंध में केन्द्र व राज्य सरकारों के द्वारा बनाए कानूनों का भी खाप पंचायतों ने मखोल उड़ाया। उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णयों के माध्यम से दिशा निर्देश दिए। हाल में राजस्थान सरकार के द्वारा 2019 में ऑनर किलिंग को रोकने के संबंध में कानून बनाया है।

Keywords : ऑनर किलिंग, खाप पंचायत, मानवाधिकर , स्वतंत्रता

प्रस्तावना

भारत एवं विश्व के कई देशों मे जाति एवं धर्म में ऐसी कई प्रथाएँ विद्यमान हैं जिनके कारण प्रति वर्ष हजारों में नवयुवक विवाहित जोड़ों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है। समाज में शिक्षा का बढ़ावा मिलने के बावजूद ऑनर किलिंग आज भी बद्स्तूर जारी है। भारत के कुछ राज्यों जिनमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में ऑनर किलिंग की घटनाएँ सबसे अधिक हुई हैं। उच्चतम न्यायालय ने भी समय समय पर खाप पंचायतों के विरूद्ध कठोर कदम उठाए हैं, लेकिन समाज में सम्मान के नाम पर कई जातियों व धर्मों में लोग अपनी ही बेटे–बेटियों को मार रहे हैं। जो वर्तमान समय में बदस्तूर जारी है। जो समाज में कलंक के साथ चुनौती है।

ऑनर किलिंग यानि सम्मान के लिए मृत्यु या इज्जत के लिए हत्या से है, ऐसे शब्द हैं जिसमें परिवार के सदस्यों द्वारा ही अपने पुत्र या पुत्रियों की हत्या सम्मान या इज्जत के नाम पर कर दी जाती है। यह भारत ही नहीं, बल्कि कई देशों में यह बुराई आज भी विद्यमान है। 'इज्जत के लिए हत्या' ऐसी हत्या है जो परिवार या जाति या धर्म या समुदाय के सदस्यों द्वारा इसलिए की जाती है कि पीडित व्यक्ति (पुरूष या महिला ने) उस परिवार, जाति, धर्म या समुदाय की इज्जत, प्रतिष्ठा या नाम पर बट्टा अपने कृत्यों से लगाया है। **सन्**1978 में डच स्कालर ऐन ने जब पहली बार 'ऑनर किलिंग' शब्द का प्रयोग किया था तब वह नहीं जानती होगी कि वह मानव सभ्यता को एक ऐसा शब्द दे रही है,जो बरसों रक्त सामंतवादिता का पर्याय बन जाएगा। करो–करी, इज्जत के नाम पर हत्या, या ऑनर किलिंग जिस नाम से पुकारा जाए समाज के माथे पर कालिख का एक रूप ही रहता है। इस प्रकार ऑनर किलिंग में प्रतिशोध पूर्ण हत्या पुरूषों द्वारा परिवार की महिला सदस्य की हत्या कर दी जाती है जिसके कारण समाज या जाति , धर्म में इज्जत पर बट्टा लगाया हो जैसे पारंपरिक विवाह न करना, जाति, धर्म से बाहर विवाह करना, बलात्कार का शिकार होना, तलाक चाहना अथवा जार संबंध कायम करना।

ऑनर किलिंग बनाम खाप पंचायत

हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाप पंचायतों का प्रचलन सदियों से रहा है। समाज में इनकी हैसियत बहुत मायने रखती है, लेकिन सरकारी कानून की नजर में इनकी कोई हैसियत नहीं रही है। इनके जरिए किए गए फैसले किसी फतवे से कम नहीं रहे, और जो फतवे के खिलाफ जाता है उसे गाँव से निकाला ,जाति निकाला, या मौत की सजा दी जाती रही है। इन्दर मलहोत्रा का कथन है कि खाप पंचायतें अपने देश में अकेले जाट समाज में 3500 बताई जाती हैं। खाप पंचायतें जब कोई जोड़ा सगोत्र अथवा गाँव के गाँव में ही प्रेम प्रसंग चला है तो उसके विरूद्ध कड़े कदम उठाने के लिए विवश हो जाते हैं क्योंकि उससे सामाजिक प्रतिष्ठा जुड़ी होती है और स्थापित आचार–विचार की अवहेलना होती है।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य में ऑनर किलिंग तथ्य– लेबनान में प्रतिवर्ष लगभग 40–50 हत्याएं इज्जत के नाम पर की जाती हैं इसी प्रकार यूरोप में एवं अमेरिका में 90 प्रतिशत इज्जत के लिए हत्याएं मुस्लिम परिवरों से संबंधित होती हैं। पेरू में लगभग 70 प्रतिशत महिलाओं की हत्या उनके पतियों द्वारा या पुरूष मित्रों द्वारा की

*सहायक प्रोफेसर – विधि संकाय, जय नारायण व्यास विश्वविधालय, जोधपुर

Dean & Head
Faculty of Law
J.N. Vyas University
Jodhpur

CONTENTS

S. No.	Topic		Page No.
1.	डॉ0 त्रिभुवन सिंह की साहित्येतिहास–दृष्टि ('हिन्दी साहित्य : एक परिचय' के विशेष संदर्भ में)	डॉ0 सन्त राम वैश्य	1
2.	हिन्दी के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों में उपभोक्ता संस्कृति के चिह्न	डॉ0 संगीता कुमारी	6
3.	मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले में गन्ना विकास कार्यक्रमों का गन्ना किसानों पर प्रभाव – एक विश्लेषणात्मक अध्ययन	डॉ0 विनोद काले	10
4.	हिन्दी–महिला उपन्यासकारों के उपन्यासों में नारी अस्मिता	डॉ0 सुनीता देवी	17
5.	माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत विभिन्न सम्प्रदायों की शिक्षिकाओं में समायोजन एवं रूचि का अध्ययन	रूबी चाहल डॉ0 मोहन लाल 'आर्य'	21
6.	भारत में महिला शिक्षा और समाज में स्थान : एक शैक्षिक अध्ययन	प्रो0 महेन्द्र प्रसाद पाण्डेय राजकुमारी गोला	26
7.	न्याय एवं जबाबदेही : भारतीय परिदृश्य में एक अध्ययन	दयानंद प्रसाद	30
8.	भारत में ऑनर किलिंग : एक चुनौती	डॉ0 शीतल प्रसाद मीना	34
9.	समकालीन हिन्दी कविता में चित्रित स्त्री छवि	डॉ0 कुलदीप सिंह मीना	37
10.	तबला का फर्रूखाबाद घराना–वादन शैलीगत विशेषताएँ	डॉ0 प्रियंका अरोड़ा डॉ0 गुरप्रीत कौर सिद्धार्थ चैटर्जी	42
11.	छत्तीसगढ़ी और हलबी के लिंग–विधान में साम्य–वैषम्य	हितेश कुमार	48
12.	महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य में योगदान	कृपा शंकर	53
13.	छत्तीसगढ़ के कमार जनजाति में गोदना कला	राज कुमार वर्मा जितेन्द्र कुमार प्रेमी	56
14.	हिन्दी के असंगत नाटक और लक्ष्मीकान्त वर्मा	डॉ0 रमेश प्रताप सिंह	61
15.	सामाजिक–आर्थिक विकास के अंतर–क्षेत्रीय असमानता में जिला दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल का एक ब्लॉक स्तरीय अध्ययन	डॉ0 रंजन सरकार	65
16.	उद्भवशतक में वर्णित प्रकृति और सौन्दर्य	डॉ0 शशि पटेल	72
17.	कानपुर महानगर में श्रमिकों के ग्रामीण–नगरीय अन्तःप्रवास प्रतिरूप का विश्लेषण	डॉ0 रत्नेश शुक्ल	76
18.	नेहरू पर्वतारोहण संस्थान : उत्तरकाशी	गीता आर्या	81
19.	विभिन्न सामाजिक–आर्थिक स्तर के आधार पर किशोरों में तनाव का तुलनात्मक अध्ययन	प्रीती कुमारी	86

Head
Faculty of Law
J.N.Vyas University
Jodhpur

20.	नरेंद्र कोहली के रामकथा पर आधारित उपन्यास में समकालीनता	डॉ0 जयलक्ष्मी एफ. पाटील	91
21.	हिंदी साहित्येतिहास में उत्तर–मध्यकाल के नामकरण की समस्या	कपिल कुमार गौतम	95
22.	बिहार में सतत् एवं समावेशी विकास पर मनरेगा का प्रभाव	प्रेम शंकर गोंड	99
23.	डॉ. राजेंद्र मोहन भटनागर के एतिहासिक उपन्यास कुली बैरिस्टर (महात्मा गाँधी)	सम्पूर्णानन्द गौतम	104
24.	हिन्दी सिनेमा में स्त्री की छवि	डॉ0 मनोज कुमार स्वामी	107
25.	वैश्विक सन्दर्भ में अनुवाद की उपादेयता	डॉ0 विकास कुमार	110
26.	प्रवासी हिन्दी साहित्य की अवधारणा एवं स्वरूप	डॉ0 अन्जु बाला	113
27.	नगर पालिका निगम दुर्ग के जलकार्य विभाग के आय–व्यय का मूल्यात्मक अध्ययन	अंकिता नामदेव डॉ0 एच0 एस0 भाटिया	116
28.	विश्व पटल पर हिन्दी और उसकी चुनौतियाँ	डॉ0 हरि नाथ	122
29.	पहाड़ों में पलायन और समकालीन हिंदी उपन्यास (उत्तराखण्ड के सम्बन्ध में)	रवि यादव	126
30.	समावेशी शिक्षा – वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चुनौतियाँ	सुगन्ध कुमार	129
31.	धमतरी नगर निगम के पेयजल व्यवस्था का विश्लेषण	मंजू गोस्वामी डॉ0 आर0 के0 पुरोहित सुभाष चन्द्राकर	135
32.	सोशल मीडिया पर सूचना की विश्वसनीयता व सामाजिक प्रभाव	डॉ0 सुधारानी सिंह	138
33.	माध्यमिक स्तर के उच्च एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले विद्यार्थियों के आत्म–प्रत्यय का तुलनात्मक अध्ययन	शिव नारायण डॉ0 रश्मि गोरे	141
34.	अरविंद–दर्शन में 'रूपांतरण' एवं 'अतिमानस' की अवधारणा	डॉ0 अनिल राय	147
35.	बद्री सिंह भाटिया के कथा–साहित्य में मनोविज्ञान	सुषमा देवी	151
36.	सूरदास और माधवदेव की रचनाओं में वात्सल्य भावना : एक अध्ययन	डॉ0 प्रीति वैश्य	155
37.	शान्ति शिक्षा एवं इसके विविध पक्षों में निहित घटक तत्व	अश्विनी कुमार पाठक एन0पी0 भोक्ता	159
38.	भारतीय संविधान में हिन्दी और राजभाषा अधिनियम	डॉ0 यामिनी राय	163
39.	आधुनिक भारत मे महिलाओं की दशा	देव कुमार	166
40.	सूर्यबाला के कथा साहित्य में चित्रित समाज के विविध आयाम	डॉ0 आशा कुमारी	170
41.	कबीर : मानुष ऐसा चाहिए	सत्येन्द्र कुमार दुबे	173
42.	स्त्री सशक्तिकरण : शक्तिस्वरूपा सशक्त सीता	सीमा दुबे	177
43.	पूर्वोत्तरीय संस्कृति में मानवीय तत्व	प्रो0 सुशील कुमार शर्मा	181

Dean & Head
Faculty of Law
J.N.Vyas University
Jodhpur

44.	बहुलतावादी संस्कृति के अग्रदूत : सिंधी कवि संत रोहल	डॉ0 चन्द्रभूषण त्रिपाठी	184
45.	इंडोनेशिया के अभिलेखों में प्रतिबिम्बित भारतीय धर्म एवं संस्कृति	हरीशंकर शर्मा	189
46.	अवध के अन्तिम शासक बादशाह वाजिद अली शाह एवं उनका शासन	डॉ0 मिथिलेश कुमार यादव	192
47.	प्रेमचन्द की कहानियों में चित्रित नैतिक मूल्य	डॉ0 अखिलेश कुमार	195
48.	चन्द्रकिरण सौनरेक्सा के उपन्यास 'वंचिता' में स्त्री जीवन	डॉ0 अखिलेश कुमार वर्मा	198
49.	वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मीडिया और राष्ट्रीय सुरक्षा	डॉ0 हेमन्त कुमार पाल डॉ0 अभय कुमार श्रीवास्तव	201
50.	प्रयोगवादी और नई कविता काल के संग्रह एवं पत्रिकाएँ	प्रो0 सुशील कुमार शर्मा	204
51.	निराला के कथा–साहित्य में विधवा–वेश्या समस्या का यथार्थ चित्रण	डॉ0 रणधीर सिंह	207
52.	बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के विशेष संदर्भ में	अभय कुमार	210
53.	संतुलित आहार की संकल्पना	डॉ0 अंजू कुमारी सिन्हा	214
54.	प्राकृतिक आपदा कारण एवं निवारण : बिहार के विशेष संदर्भ में	गुफराना नाहिद	218
55.	प्रेस की स्वायत्तता : वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक समीक्षात्मक अध्ययन	मोनिका कुमारी	222
56.	भारतीय संविधान के अन्तर्गत मौलिक अधिकारों के संदर्भ में विधानपालिका और न्यायपालिका की भूमिका एवं तनाव	डॉ0 नवीन प्रसाद	225
57.	भारत की विदेश नीति की निरंतरता एवं परिवर्तन : राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में	राजीव रंजन कुमार	229
58.	"वैदिक साहित्य में निदर्शित मांसाहर–निषेध एवं उसके सेवन के दोष"	डॉ0 एम0 एल0 यादव	233
59.	बिहार के प्रवासी मजदूरों की समस्याएँ एवं चुनौतियाँ	डॉ0 राकेश रंजन	236
60.	हिंदी के जातीय साहित्य में मुस्लिम समाज एवं संस्कृति का प्रभाव	डॉ0 श्रवण कुमार	239

Dean & Head
Faculty of Law
J.N.Vyas University
Jodhpur

GOVT. OF INDIA- RNI NO. UPBIL/2014/56766
UGC Approved Care Listed Journal
ISSN 2348-2397

शोध सरिता

An International Multidisciplinary Quarterly
Bilingual Peer Reviewed Refereed Research Journal

• Vol. 7 • Issue 25 • January to March 2020

3.4.5/6
SPM

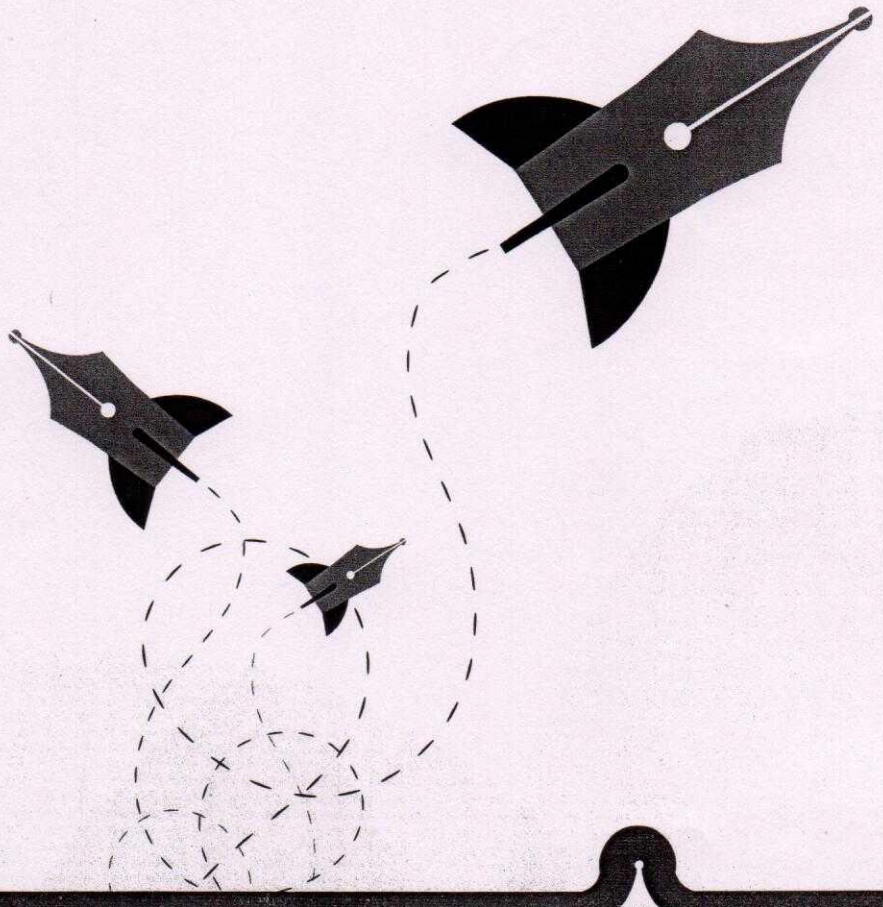

Editor in Chief
Dr. Vinay Kumar Sharma
D. Litt. - Gold Medalist

sanCHar
Educational & Research Foundation

ISSN - 2348-2397
APPROVED UGC CARE

SHODH SARITA

SHODH SARITA
Vol. 7, Issue 25, January-March, 2020
Page Nos. 34-36

AN INTERNATIONAL BILINGUAL PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

भारत में ऑनर किलिंग : एक चुनौती

❐ डॉ0 शीतल प्रसाद मीना*

शोध सारांश

वर्तमान समय में भारत सहित विश्व के कई देशों में सम्मान के नाम पर दो वयस्कों द्वारा एक ही गोत्र परिवार, समाज या धर्म में विवाह करने पर हत्या करने की घटनाएँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। इससे व्यक्ति के जीने के अधिकार से वंचित हो जाता है तथा संवैधानिक तथा विधिक अधिकारों का हनन भी होता है। इस संबंध में केन्द्र व राज्य सरकारों के द्वारा बनाए कानूनों का भी खाप पंचायतों ने मखोल उड़ाया। उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण निर्णयों के माध्यम से दिशा निर्देश दिए। हाल में राजस्थान सरकार के द्वारा 2019 में ऑनर किलिंग को रोकने के संबंध में कानून बनाया है।

Keywords: ऑनर किलिंग, खाप पंचायत, मानवाधिकर , स्वतंत्रता

प्रस्तावना

भारत एवं विश्व के कई देशों मे जाति एवं धर्म में ऐसी कई प्रथाएँ विद्यमान हैं जिनके कारण प्रति वर्ष हजारों में नवयुवक विवाहित जोड़ों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ता है। समाज में शिक्षा का बढ़ावा मिलने के बावजूद ऑनर किलिंग आज भी बद्स्तूर जारी है। भारत के कुछ राज्यों जिनमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में ऑनर किलिंग की घटनाएँ सबसे अधिक हुई हैं। उच्चतम न्यायालय ने भी समय समय पर खाप पंचायतों के विरूद्ध कठोर कदम उठाए हैं, लेकिन समाज में सम्मान के नाम पर कई जातियों व धर्मों में लोग अपनी ही बेटे–बेटियों को मार रहे हैं। जो वर्तमान समय में बदस्तूर जारी है। जो समाज में कलंक के साथ चुनौती है।

ऑनर किलिंग यानि सम्मान के लिए मृत्यु या इज्जत के लिए हत्या से है, ऐसे शब्द हैं जिसमें परिवार के सदस्यों द्वारा ही अपने पुत्र या पुत्रियों की हत्या सम्मान या इज्जत के नाम पर कर दी जाती है। यह भारत ही नहीं, बल्कि कई देशों में यह बुराई आज भी विद्यमान है। 'इज्जत के लिए हत्या' ऐसी हत्या है जो परिवार या जाति या धर्म या समुदाय के सदस्यों द्वारा इसलिए की जाती है कि पीडित व्यक्ति (पुरूष या महिला ने) उस परिवार, जाति, धर्म या समुदाय की इज्जत, प्रतिष्ठा या नाम पर बट्टा अपने कृत्यों से लगाया है। **सन्**1978 में डच स्कालर ऐन ने जब पहली बार 'ऑनर किलिंग' शब्द का प्रयोग किया था तब वह नहीं जानती होगी कि वह मानव सभ्यता को एक ऐसा शब्द दे रही है,जो बरसों रक्त सामंतवादिता का पर्याय बन जाएगा। करो–करी, इज्जत के नाम पर हत्या, या ऑनर किलिंग जिस नाम से पुकारा जाए समाज के माथे पर कालिख का एक रूप ही रहता है। इस प्रकार ऑनर किलिंग में प्रतिशोध पूर्ण हत्या पुरूषों द्वारा परिवार की महिला सदस्य की हत्या कर दी जाती है जिसके कारण समाज या जाति , धर्म में इज्जत पर बट्टा लगाया हो जैसे पारंपरिक विवाह न करना, जाति, धर्म से बाहर विवाह करना, बलात्कार का शिकार होना, तलाक चाहना अथवा जार संबंध कायम करना।

ऑनर किलिंग बनाम खाप पंचायत

हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खाप पंचायतों का प्रचलन सदियों से रहा है। समाज में इनकी हैसियत बहुत मायने रखती है, लेकिन सरकारी कानून की नजर में इनकी कोई हैसियत नहीं रही है। इनके जरिए किए गए फैसले किसी फतवे से कम नहीं रहे, और जो फतवे के खिलाफ जाता है उसे गाँव से निकाला ,जाति निकाला, या मौत की सजा दी जाती रही है। इन्दर मलहोत्रा का कथन है कि खाप पंचायतें अपने देश में अकेले जाट समाज में 3500 बताई जाती हैं। खाप पंचायतें जब कोई जोड़ा सगोत्र अथवा गाँव के गाँव में ही प्रेम प्रसंग चला है तो उसके विरूद्ध कड़े कदम उठाने के लिए विवश हो जाते हैं क्योंकि उससे सामाजिक प्रतिष्ठा जुड़ी होती है और स्थापित आचार–विचार की अवहेलना होती है।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य में ऑनर किलिंग तथ्य– लेबनान में प्रतिवर्ष लगभग 40–50 हत्याएं इज्जत के नाम पर की जाती हैं इसी प्रकार यूरोप में एवं अमेरिका में 90 प्रतिशत इज्जत के लिए हत्याएं मुस्लिम परिवरों से संबंधित होती हैं। पेरू में लगभग 70 प्रतिशत महिलाओं की हत्या उनके पतियों द्वारा या पुरूष मित्रों द्वारा की

*सहायक प्रोफेसर – विधि संकाय, जय नारायण व्यास विश्वविधालय, जोधपुर

CONTENTS

S. No.	Topic		Page No.
1.	डॉ0 त्रिभुवन सिंह की साहित्येतिहास–दृष्टि ('हिन्दी साहित्य : एक परिचय' के विशेष संदर्भ में)	डॉ0 सन्त राम वैश्य	1
2.	हिन्दी के कुछ महत्वपूर्ण उपन्यासों में उपभोक्ता संस्कृति के चिह्न	डॉ0 संगीता कुमारी	6
3.	मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले में गन्ना विकास कार्यक्रमों का गन्ना किसानों पर प्रभाव – एक विश्लेषणात्मक अध्ययन	डॉ0 विनोद काले	10
4.	हिन्दी–महिला उपन्यासकारों के उपन्यासों में नारी अस्मिता	डॉ0 सुनीता देवी	17
5.	माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत विभिन्न सम्प्रदायों की शिक्षिकाओं में समायोजन एवं रूचि का अध्ययन	रूबी चाहल डॉ0 मोहन लाल 'आर्य'	21
6.	भारत में महिला शिक्षा और समाज में स्थान : एक शैक्षिक अध्ययन	प्रो0 महेन्द्र प्रसाद पाण्डेय राजकुमारी गोला	26
7.	न्याय एवं जबाबदेही : भारतीय परिदृश्य में एक अध्ययन	दयानंद प्रसाद	30
8.	भारत में ऑनर किलिंग : एक चुनौती	डॉ0 शीतल प्रसाद मीना	34
9.	समकालीन हिन्दी कविता में चित्रित स्त्री छवि	डॉ0 कुलदीप सिंह मीना	37
10.	तबला का फर्रूखाबाद घराना–वादन शैलीगत विशेषताएँ	डॉ0 प्रियंका अरोड़ा डॉ0 गुरप्रीत कौर सिद्धार्थ चैटर्जी	42
11.	छत्तीसगढ़ी और हलबी के लिंग–विधान में साम्य–वैषम्य	हितेश कुमार	48
12.	महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य में योगदान	कृपा शंकर	53
13.	छत्तीसगढ़ के कमार जनजाति में गोदना कला	राज कुमार वर्मा जितेन्द्र कुमार प्रेमी	56
14.	हिन्दी के असंगत नाटक और लक्ष्मीकान्त वर्मा	डॉ0 रमेश प्रताप सिंह	61
15.	सामाजिक–आर्थिक विकास के अंतर–क्षेत्रीय असमानता में जिला दक्षिण दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल का एक ब्लॉक स्तरीय अध्ययन	डॉ0 रंजन सरकार	65
16.	उद्भवशतक में वर्णित प्रकृति और सौन्दर्य	डॉ0 शशि पटेल	72
17.	कानपुर महानगर में श्रमिकों के ग्रामीण–नगरीय अन्तःप्रवास प्रतिरूप का विश्लेषण	डॉ0 रत्नेश शुक्ल	76
18.	नेहरू पर्वतारोहण संस्थान : उत्तरकाशी	गीता आर्या	81
19.	विभिन्न सामाजिक–आर्थिक स्तर के आधार पर किशोरों में तनाव का तुलनात्मक अध्ययन	प्रीती कुमारी	86

20.	नरेंद्र कोहली के रामकथा पर आधारित उपन्यास में समकालीनता	डॉ0 जयलक्ष्मी एफ. पाटील	91
21.	हिंदी साहित्येतिहास में उत्तर–मध्यकाल के नामकरण की समस्या	कपिल कुमार गौतम	95
22.	बिहार में सतत् एवं समावेशी विकास पर मनरेगा का प्रभाव	प्रेम शंकर गोंड	99
23.	डॉ. राजेंद्र मोहन भटनागर के एतिहासिक उपन्यास कुली बैरिस्टर (महात्मा गाँधी)	सम्पूर्णानन्द गौतम	104
24.	हिन्दी सिनेमा में स्त्री की छवि	डॉ0 मनोज कुमार स्वामी	107
25.	वैश्विक सन्दर्भ में अनुवाद की उपादेयता	डॉ0 विकास कुमार	110
26.	प्रवासी हिन्दी साहित्य की अवधारणा एवं स्वरूप	डॉ0 अन्जु बाला	113
27.	नगर पालिका निगम दुर्ग के जलकार्य विभाग के आय–व्यय का मूल्यात्मक अध्ययन	अंकिता नामदेव डॉ0 एच0 एस0 भाटिया	116
28.	विश्व पटल पर हिन्दी और उसकी चुनौतियाँ	डॉ0 हरि नाथ	122
29.	पहाड़ों में पलायन और समकालीन हिंदी उपन्यास (उत्तराखण्ड के सम्बन्ध में)	रवि यादव	126
30.	समावेशी शिक्षा – वर्तमान परिप्रेक्ष्य में चुनौतियाँ	सुगन्ध कुमार	129
31.	धमतरी नगर निगम के पेयजल व्यवस्था का विश्लेषण	मंजू गोस्वामी डॉ0 आर0 के0 पुरोहित सुभाष चन्द्राकर	135
32.	सोशल मीडिया पर सूचना की विश्वसनीयता व सामाजिक प्रभाव	डॉ0 सुधारानी सिंह	138
33.	माध्यमिक स्तर के उच्च एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि वाले विद्यार्थियों के आत्म–प्रत्यय का तुलनात्मक अध्ययन	शिव नारायण डॉ0 रश्मि गोरे	141
34.	अरविंद–दर्शन में 'रूपांतरण' एवं 'अतिमानस' की अवधारणा	डॉ0 अनिल राय	147
35.	बद्री सिंह भाटिया के कथा–साहित्य में मनोविज्ञान	सुषमा देवी	151
36.	सूरदास और माधवदेव की रचनाओं में वात्सल्य भावना : एक अध्ययन	डॉ0 प्रीति वैश्य	155
37.	शान्ति शिक्षा एवं इसके विविध पक्षों में निहित घटक तत्व	अश्विनी कुमार पाठक एन0पी0 भोक्ता	159
38.	भारतीय संविधान में हिन्दी और राजभाषा अधिनियम	डॉ0 यामिनी राय	163
39.	आधुनिक भारत मे महिलाओं की दशा	देव कुमार	166
40.	सूर्यबाला के कथा साहित्य में चित्रित समाज के विविध आयाम	डॉ0 आशा कुमारी	170
41.	कबीर : मानुष ऐसा चाहिए	सत्येन्द्र कुमार दुबे	173
42.	स्त्री सशक्तिकरण : शक्तिस्वरूपा सशक्त सीता	सीमा दुबे	177
43.	पूर्वोत्तरीय संस्कृति में मानवीय तत्व	प्रो0 सुशील कुमार शर्मा	181

44.	बहुलतावादी संस्कृति के अग्रदूत : सिंधी कवि संत रोहल	डॉ0 चन्द्रभूषण त्रिपाठी	184
45.	इंडोनेशिया के अभिलेखों में प्रतिबिम्बित भारतीय धर्म एवं संस्कृति	हरीशंकर शर्मा	189
46.	अवध के अन्तिम शासक बादशाह वाजिद अली शाह एवं उनका शासन	डॉ0 मिथिलेश कुमार यादव	192
47.	प्रेमचन्द की कहानियों में चित्रित नैतिक मूल्य	डॉ0 अखिलेश कुमार	195
48.	चन्द्रकिरण सौनरेक्सा के उपन्यास 'वंचिता' में स्त्री जीवन	डॉ0 अखिलेश कुमार वर्मा	198
49.	वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मीडिया और राष्ट्रीय सुरक्षा	डॉ0 हेमन्त कुमार पाल डॉ0 अभय कुमार श्रीवास्तव	201
50.	प्रयोगवादी और नई कविता काल के संग्रह एवं पत्रिकाएँ	प्रो0 सुशील कुमार शर्मा	204
51.	निराला के कथा–साहित्य में विधवा–वेश्या समस्या का यथार्थ चित्रण	डॉ0 रणधीर सिंह	207
52.	बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के विशेष संदर्भ में	अभय कुमार	210
53.	संतुलित आहार की संकल्पना	डॉ0 अंजू कुमारी सिन्हा	214
54.	प्राकृतिक आपदा कारण एवं निवारण : बिहार के विशेष संदर्भ में	गुफराना नाहिद	218
55.	प्रेस की स्वायत्तता : वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक समीक्षात्मक अध्ययन	मोनिका कुमारी	222
56.	भारतीय संविधान के अन्तर्गत मौलिक अधिकारों के संदर्भ में विधानपालिका और न्यायपालिका की भूमिका एवं तनाव	डॉ0 नवीन प्रसाद	225
57.	भारत की विदेश नीति की निरंतरता एवं परिवर्तन : राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में	राजीव रंजन कुमार	229
58.	''वैदिक साहित्य में निदर्शित मांसाहर–निषेध एवं उसके सेवन के दोष''	डॉ0 एम0 एल0 यादव	233
59.	बिहार के प्रवासी मजदूरों की समस्याएँ एवं चुनौतियाँ	डॉ0 राकेश रंजन	236
60.	हिंदी के जातीय साहित्य में मुस्लिम समाज एवं संस्कृति का प्रभाव	डॉ0 श्रवण कुमार	239

UGC APPROVED
CARE LISTED JOURNAL

ISSN 2229-3620

GOVT. OF INDIA RNI NO. - UPBIL/2015/62096

शोध संचार बुलेटिन

AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY QUARTERLY BILINGUAL PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

★ Vol. 10 ★ Issue [illegible] ★ January to March 2020

SPM
3.4.5 | 7

Dean & Head
Faculty of Law
J.N.Vyas University
Jodhpur

Editor in Chief
Dr. Vinay Kumar Sharma
D. Litt. - Gold Medalist

Sanchar
Educational & Research Foundation

GOVT. OF INDIA RNI NO. - UPBIL/2015/62096

ISSN-2229-3620

UGC APPROVED
CARE LISTED JOURNAL

JOURNAL OF
ARTS, HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPILANARY QUARTERLY BILINGUAL PEER REVIEWED REFERED RESEARCH JOURNAL

शोध संचार बुलेटिन

• Vol. 10 • Issue 37 • January to March 2020

संपादक मण्डल

प्रो० योगेन्द्र प्रताप सिंह
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

प्रो० सुशील कुमार शर्मा
मिजोरम विश्वविद्यालय, मिजोरम

प्रो० अरूण कुमार भगत
महात्मा गाँधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतीहारी बिहार

प्रो० हेमराज सुन्दर
महात्मा गाँधी संस्थान, मोका, मॉरीशस

प्रो० संतोष कुमार शुक्ला
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

प्रो० पवन शर्मा
मेरठ विश्वविद्यालय, मेरठ

प्रो० करूणा शंकर उपाध्याय
मुंबई विश्वविद्यालय, मुंबई

प्रो० अरविन्द कुमार झा
बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ

प्रो० पदम कान्त
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

प्रो० अर्जुन चव्हाण
शिवाजी विश्वविद्यालय, कोल्हापुर, महाराष्ट्र

प्रो० श्रद्धा सिंह
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी

प्रो० नागेन्द्र अम्बेडकर सोले
केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राजस्थान

प्रधान संपादक

डॉ. विनय कुमार शर्मा
अध्यक्ष
संचार एजुकेशनल एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन, लखनऊ

संचार एजुकेशनल एण्ड रिसर्च फाउण्डेशन, लखनऊ (उ0प्र0), भारत द्वारा प्रकाशित

Dean & Head
Faculty of Law
J.N.Vyas University
Jodhpur

CONTENTS

S. No.	Topic		Page No.
1.	हिन्दी का प्रयोजन मूलक स्वरूप	डॉ0 सन्त राम वैश्य	1
2.	धर्म की मनोवैज्ञानिक प्रकृति एवं कार्य	दयानंद प्रसाद	6
3.	आक्रोश, प्रतिरोध व विद्रोह का स्वर : दलित कविता	डॉ0 कुलदीप सिंह मीना	9
4.	सिलिकोसिस पीड़ित श्रमिक एवं मानवाधिकार	डॉ0 शीतल प्रसाद मीना	14
5.	सितार साधिका–कु.चन्द्रकान्ता खोसला–कलात्मक उपलब्धियाँ	डॉ0 गुरप्रीत कौर मनदीप सिंह डॉ0 प्रियंका अरोड़ा	18
6.	सार्त्र और मार्क्सवाद : एक समीक्षात्मक अध्ययन	श्याम रंजन पाण्डेय	22
7.	विभिन्न सामाजिक–आर्थिक स्तर के आधार पर ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के किशोरों में तनाव का तुलनात्मक अध्ययन	प्रीती कुमारी	25
8.	आधुनिक हिंदी कविता और भारतीय जनभावना	डॉ0 जयलक्ष्मी एफ. पाटील	30
9.	पंचायतीराज में न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं महिला प्रतिनिधित्व एक अवलोकनात्मक अध्ययन	हनुमन्त सिंह	34
10.	आदिवासी विमर्श : अस्तित्व का संकट बनाम संघर्ष की चेतना	कपिल कुमार गौतम	38
11.	मन्दबुद्धि बच्चों के समायोजन सम्बन्धी समस्याएं	डॉ0 ममता सिंह	42
12.	डॉ. राजेन्द्र मोहन भटनागर के ऐतिहासिक उपन्यासों में मीरा (स्त्री चेतना के संदर्भ में)	सम्पूर्णानन्द गौतम	48
13.	महात्मा गांधी की कृषि–नीति और भवानीप्रसाद मिश्र की कविता	डॉ0 मनोज कुमार स्वामी	51
14.	मध्यप्रदेश राज्य के उज्जैन संभाग के माध्यमिक स्तर पर कार्यरत शहरी एवं ग्रामीण शिक्षकों की व्यावसायिक प्रतिबद्धता एवं आत्मविश्वास का अध्ययन	अनिल बाबू डॉ0 अराधना सेठी	55
15.	पर्यावरण प्रदूषण और जीवन जीने का अधिकार	डॉ0 सुधारानी सिंह	60
16.	भारत में नक्सलवाद की समस्या	सत्येन्द्र सिंह	63
17.	समाचार पत्र एवं सूचना के अधिकार में अंतर्संबंध : छत्तीसगढ़ के शासकीय विभागों को पत्रकार, शासकीय सेवक और सामाजिक कार्यकर्ता से मिले आरटीआई आवेदनों का तुलनात्मक अध्ययन	सुधीर कुमार उपाध्याय डॉ0 नरेंद्र त्रिपाठी	68
18.	वैश्विक आर्थिक मन्दी व भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव	डॉ0 जी.एल. मीणा	73
19.	मानवीय स्वास्थ्य हेतु पादपों की उपादेयता	डॉ0 आदित्य शर्मा डॉ0 संजय तोमर	79
20.	डॉ0 कन्हैया सिंह के साहित्यिक निबन्ध	सत्येन्द्र कुमार दुबे	82

Head
Faculty of Law
J.N.Vyas University
Jodhpur

GOVT. OF INDIA RNI NO.: UPBIL/2015/62096

UGC Approved Care Listed Journal

ISSN 2229-3620

SIT

SHODH SANCHAR Bulletin

An International
Multidisciplinary
Quarterly Bilingual
Peer Reviewed
Refereed
Research Journal

3.4.5/7
SPM

Head
Faculty of Law
J.N.Vyas University
Jodhpur

Vol. 10

Issue 39

July to September 2020

Editor in Chief
Dr. Vinay Kumar Sharma
D. Litt. – Gold Medalist

sanchar
Educational & Research Foundation

UGC APPROVED
CARE LISTED JOURNAL
GOVT. OF INDIA RNI NO. - UPBIL/2015/62096

ISSN No. 2229-3620

SHODH SANCHAR Bulletin

AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY QUARTERLY BILINGUAL
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

* Vol. 10 * Issue 39 * July - September 2020

EDITORIAL BOARD

Prof. Surya Prasad Dixit
Jawahar Lal Nehru University, New Delhi

Prof. Shraddha Singh
Banaras Hindu University

Prof. Santosh Kumar Shukla
Jawahar Lal Nehru University, New Delhi

Prof. Pawan Sharma
Meerut University, Meerut

Prof. Karuna Shankar Upadhyay
Mumbai University, Mumbai

Prof. Hemraj Sundar
Mahatma Gandhi Sansthan, Moka, Mauritius

Prof. Abdul Alim
Aligarh Muslim University, Aligarh

Prof. Susheel Kumar Sharma
Mizoram University, Mizoram

Prof. Padam Kant
University of Lucknow

Prof. Arbind Kumar Jha
BBA Central University, Lucknow

Prof. Sheela Mishra
Usmania University, Hyderabad

Prof. Nagendra Ambedkar Sole
Central University of Rajasthan

EDITOR IN CHIEF

Dr. Vinay Kumar Sharma
Chairman
Sanchar Educational & Research Foundation, Lucknow

Dean & Head
Faculty of Law
J.N.Vyas University
Jodhpur

PUBLISHED BY

sanchar
Educational & Research Foundation

CONTENTS

S. No.	Topic		Page No.
1.	SOCIAL WELL-BEING IN RELATION TO ALIENATION AMONG UNIVERSITY STUDENTS	Prof. Mohd. Ilyas Khan (Retd.)	1
2.	IMPACT OF MID DAY MEAL SCHEME ON ENROLLMENT ISSUES IN PRIMARY SCHOOLS OF GWALIOR CITY	Neha Thakur Dr. P.K. Gupta Dr. Rajendra K. Khatik	7
3.	EMERGING TRENDS IN GROWTH AND RISK OF AGRICULTURE SECTOR IN BUNDELKHAND REGION OF UTTAR PRADESH	Sanjeev Kumar	14
4.	CONSUMER BUYING BEHAVIOUR IN TELECOMMUNICATION SECTOR IN INDIA : A REVIEW PAPER	Praveen Kumar Rai Dr. Vijay Kumar	21
5.	SERVICE QUALITY, TOURIST SATISFACTION AND REVISIT INTENTION : STUDY OF VISITORS IN JAIPUR	Sujay Vikram Singh Kuldeep Singh Rajeev Ranjan	28
6.	IMPACT OF COVID-19 ON HOSPITALITY INDUSTRY : EMPLOYEES' PERSPECTIVE IN INDIA	Parul Gupta Dr. Priya Singh Prof. (Dr.) Aparna Raj	37
7.	A STUDY OF CONSUMER BEHAVIOUR FOR SERVICES PROVIDED BY BANKING SECTOR.	Poonam Shekhawat Dr. Monty Kanodia	44
8.	MEASURING E-DEMOCRACY & DIGITAL GOVERNMENT : COVID-19	Dr. Ekta Meena	47
9.	AN OVERVIEW OF QURANIC REFERENCES IN PROPHETIC BIOGRAPHY BY ORIENTALISTS	Danish Punjabi	53
10.	ACUTE TENSION BOTH ON FIELD AND OFF FIELD BETWEEN INDIA AND PAKISTAN CRICKET : A GAME OF A STRENGTHENING BOND BETWEEN INDIA AND PAKISTAN	Sanjay Verma Mrs. Jasmeet Kaur Jagatar Singh	58
11.	KERALA THE 'HAVEN' OF MIGRANT WORKERS : MYTH OR REALITY?	Dr. G. Geethika	61
12.	TEACHER'S ATTITUDE TOWARDS ICT (INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGY)	Suman Jana Santanu Naskar Surajit Saha	66
13.	LIFELONG LEARNING OF BIOLOGY CONCEPTS :- SCIENCE PROCESS APPROACH AS A POSSIBLE SOLUTION	Neetika Sharma	72

Head
Faculty of Law
J.N.Vyas University
Jodhpur

14.	QUALITY EDUCATION IN THE PANDEMIC TIMES : ALTERNATIVE ACADEMIC CALENDAR I	Dr. Amit Ahuja Ms. Shelly Manchanda	77
15.	SIGNIFICANCE OF ETHNOGRAPHIC RESEARCH IN EDUCATION WITH ITS EDUCATIONAL IMPLICATIONS	Vandana	82
16.	REVOLUTIONARY LINE TO BUSINESS IN THE UPCOMING SCENARIO	Dr. Versha Mohindra	86
17.	POLICY RESPONSE ON UNFREEDOM FOR YOUNG ADOLESCENT GIRLS WITH DISABILITIES IN INDIA	Pankaj Kumar Soni	91
18.	AN EMPIRICAL INVESTIGATION ON EFFECTIVENESS OF TRAINING PROGRAMME WITH SPECIAL REFERENCE TO KOTHARI SARAF PRIVATE LIMITED	Dr. Santosh Parakh Dr. Naresh E Dr. Neelkanth Dhone	98
19.	THE ROLE OF POLICE IN COVID-19 SITUATION : VARIOUS CONTEXTS	Dr. Anil Kumar	105
20.	THE RIGOR AND ETHICS OF EDUCATIONAL RESEARCH	Dr. Amit Ahuja	110
21.	THE CORRELATION BETWEEN HAPPINESS AND IDEOLOGY: A STUDY OF LEFT AND RIGHT WING IN PUNJAB.	Dr. Jagmeet Bawa Mrs. Pallavi Khanna	114
22.	HOW GREEN IS THE CONSUMER? A STUDY OF GREEN PURCHASE BEHAVIOUR	Dr. Sandeep Bhardwaj	122
23.	IMPACT EVALUATION OF COVID-19 PANDEMIC ON THE PERFORMANCE OF MSMES IN INDIA-CONCURRENT PROBLEM AND FUTURE PROSPECTS	Dr. Dinesh Prasad	126
24.	CORONAVIRUS (THE WORLD PANDEMIC) AND INDIA - A BASIC INFORMATION	Dr. Ajeet Kumar Maurya	131
25.	IMPACT OF SMALL SCALE AND COTTAGE INDUSTRIES ON RURAL DEVELOPMENT IN SAGAR DISTRICT, MADHYA PRADESH, INDIA	Ajay Kumar Verma R.K. Shrivastri	136
26.	IMPACT OF MEDIA ON TRIBALS (ADIVASIS) OF BALAGHAT, M.P. : A CASE STUDY	Dr. Kinshuk Pathak	146
27.	PRIMARY PRODUCTIVITY AND PLANKTONIC BIOMASS IN SEVEN SELECTED SITES OF GANGA RIVER WITHIN HARIDWAR CITY	Sushil Bhadula Mohit Kumar B.D. Joshi	152
28.	INCLUSIVE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF PRIMITIVE VULNERABLE TRIBAL GROUPS WITH REFERENCE TO KORAGAS OF KASARAGOD	Dr. Vijaya Kumari. K	157

Dean & Head
Faculty of Law
J.N.Vyas University
Jodhpur

29.	LITERACY RATE AND PARTICIPATION OF SCHEDULE TRIBE TEACHERS IN EDUCATION : AN EMPIRICAL STUDY	Anil Kumar Yadav Dr. Pradeep Kumar Singh	163
30.	THE WORKING CONDITION OF SCHEDULED CAST WOMEN AGRICULTURAL LABOUR IN SOLAPUR DISTRICT	Prof. G.S. Kamble Shri. Shailendra Sonawale	169
31.	REDEFINING THE TEACHING-LEARNING PROCESS IN THE 21ST CENTURY	Dr Ila Rathor	174
32.	HAND-EYE COORDINATION ON INTELLECTUALLY DISABLED CHILDREN –REGULAR PHYSICAL EXERCISES	Dr. S. Jagadeeswari	177
33.	OPERATIONAL MODE OF NGO'S DURING COVID- 19 PANDEMICS : A CASESTUDY OF MANAV SEWA SAMITI, ABOHAR, PUNJAB	Richa Sharma Dr. Sakshi Angi	182
34.	POLITICAL PHILOSOPHY OF LOKMANYA BAL GANGADHAR TILAK : A STUDY OF HIS IDEAS OF NATIONALISM	Dr. Badal Sarkar	186
35.	BACKWARD CLASSES : CONSTRUCTING CRITERIA OF BACKWARDNESS	Dr. Nagendra Prasad Verma	191
36.	ALEXA A VALUE INNOVATION : BLUE OCEAN STRATEGY	Prof. Pooja Darda Dr. Mansi Kapoor Dr. R.M. Chitnis	195
37.	AN EMPIRICAL STUDY ON CONTENT AND LANGUAGE OF JAI JAWAN PROGRAMME OF NDTV INDIA	Adarsh Kumar	202
38.	IS SOCIAL MEDIA DOING MORE HARM THAN GOOD?	Namita Verma Dr. Usha Rana	207
39.	DETERMINANTS OF EXTERNAL COMMERCIAL BORROWING	Mr. Ramakant Shukla	212
40.	EDUCATIONAL STATUS AMONG THE SCHEDULED TRIBES AND SCHEDULED CASTES OF CHHATTISGARH STATE : AN ANALYSIS	Rajkumar Nagwanshee Sambhaji Kisan Kadam	218
41.	THE ANALYTICAL STUDY OF THE E-GOVERNANCE TO THE REFERENCE OF TOURISM	Chandana Sharma	224
42.	LIFELONG LEARNING IN THE GLOBAL PERSPECTIVE	Dr. Usashi Kundu (De)	228
43.	JUDGING THE JUDGES?	Dr. Sheetal Prasad Meena	233

Dean & Head
Faculty of Law
J.N.Vyas University
Jodhpur

ISSN - 2229-3620
APPROVED UGC CARE
SIT

SHODH SANCHAR BULLETIN
Vol. 10, Issue 39, July-September 2020
Page Nos. 233-237

AN INTERNATIONAL BILINGUAL PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

JUDGING THE JUDGES?

❒ Dr. Sheetal Prasad Meena*

ABSTRACT

The Constitution provides for custodians in the form of legislature, executive and judiciary to protect will of the people. Needless to say, the custodian must be accountable to the public in exercise of their public duty. The Indian Constitution has provided for a complex web of checks and balances to ensure 'accountability' and 'responsibility' of every public institution and public functionary. Legislature and executive are directly made accountable through the system of universal adult suffrage. However, it is often found a challenge to make the judiciary accountable for misconduct. Judges enjoy judicial immunity and are not required to explain their conduct while acting in a judicial capacity. They are unaccountable to the public or to any other branch of government. Considering the fact that judges are responsible to keep a check on the abrogation of fundamental right of the citizens by other custodians, in their role as sentinel of the qui vive, the question that rightly arises is who will judge the judges? The author, through this article analyses this conundrum and tries to arrive at solutions that are the need of the hour to ensure judicial accountability while preserving judicial integrity and independence.

Keywords : judicial accountability, responsibility, judicial integrity, Independence of judiciary, Justice Delayed and justice denied

Introduction

"…however good a Constitution may be, it is sure to turn out bad because those who are called to work it, happen to be a bad lot. However bad a Constitution may be, it may turn out to be good if those who are called to work it, happen to be a good lot.

…The Constitution can provide only the organs of State such as the Legislature, the Executive and the Judiciary. The factors on which the working of those organs of the State depends are the people and the political parties they will set up as their instruments to carry out their wishes and their politics."

Dr. B.R. Ambedkar

These words of Dr. B.R. Ambedkar are crucial to understand the significance of accountability in public life especially as custodians of the Constitution. "Accountability" and "post" both are associated with each other like Sun and Shadow, Life and Death, Body and Soul, and Right and Duty. With this understanding, the framers of Constitution made the concept as a foundation stone of the Constitution's building. When we go through the provisions of Constitution, we get the idea of foresightedness of the framers of the Constitution because even the judiciary has been made accountable for it's functions and duties. In a democracy, every public authority and official should be accountable for their functions and duties. In previous times, accountability was understood only in the realm of its applicability to elected representatives who had to be accountable to their constituents.

The concept of judicial accountability has gained significance in modern times. Hence, the judges should not be treated as exception to this because accountability and duty both co-exist and one cannot survive without

*Assistant Professor - Faculty of Law, Jai Narain Vyas University, Jodhpur (Raj.)

Dean & Head
Faculty of Law
J.N.Vyas University
Jodhpur

GOVT. OF INDIA- RNI NO. UPBIL/2014/56766 ISSN 2348-2397
UGC Approved Care Listed Journal

SIS

Shodh Sarita

An International Multidisciplinary Quarterly Bilingual Peer Reviewed Refereed Research Journal

• Vol. 7 • Issue 27 • July to September 2020

3.45/8
5PM

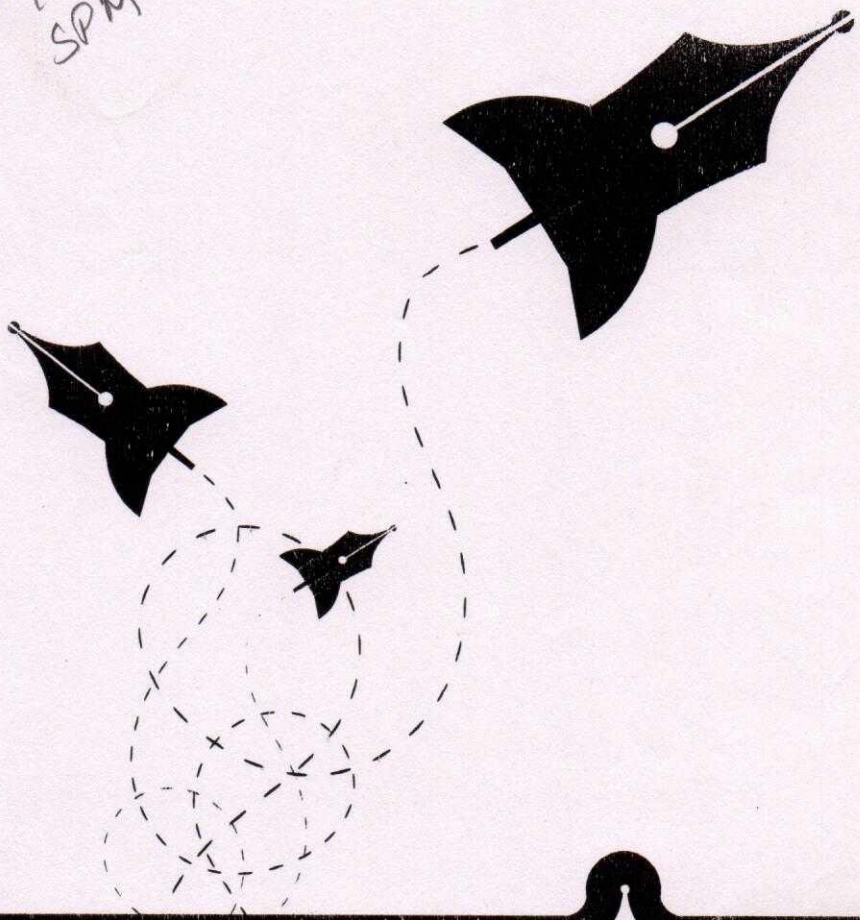

Dean & Head
Faculty of Law
J.N.Vyas University
Jodhpur

Editor in Chief
Dr. Vinay Kumar Sharma
D. Litt. - Gold Medalist

sanchar
Educational & Research Foundation

GOVT. OF INDIA- RNI NO. UPBIL/2014/56766
UGC Approved Care Listed Journal

ISSN No. 2348-2397

Shodh Sarita

AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY QUARTERLY BILINGUAL
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

• Vol. 7 • Issue 27 • July - September 2020

EDITORIAL BOARD

3.4

Prof. Surya Prasad Dixit
University of Lucknow, Lucknow

Prof. Parmeshwari Sharma
University of Jammu, Jammu

Prof. Kumud Sharma
Delhi University, Delhi

Prof. Ram Prasad Bhatt
Hamburg University, Germany

Prof. Sudheer Pratap singh
Jawahar Lal Nehru University, New Delhi

Prof. Girish Pant
Jamia Millia Islamia University, New Delhi

Prof. S. Chelliah
Madurai Kamraj University, Madurai

Prof. Ajay Kumar Bhatt
Amity University, Haryana

Prof. Pavitar Parkash Singh
Lovely Professional Universiy, Punjab

Prof. M.P. Sharma
Jamia Millia Islamia University, New Delhi

EDITOR IN CHIEF

Dr. Vinay Kumar Sharma
Chairman
Sanchar Educational & Research Foundation, Lucknow

an & Head
Faculty of Law
J.N.Vyas University
Jodhpur

PUBLISHED BY

sanchar
Educational & Research Foundation

ı Saini harma	82	27.	Guru Nanak Dev Ji's Philosophy : Impact on the Contemporary Era and Beyond	Dr. Ila Rathor	160
ı Hmar	88	28.	A Comparative Study on Cardiovascular Endurance between Male Gymmer and Soccer Athletes	Sanjay Verma Aqil Rasool	164
h Hilal ırotriya	93	29.	A RESEARCH PAPER ON POST COVID-19---ECONOMIC SCENARIO OF PUNJAB AND ROAD MAP FOR THE FUTURE	Richa Sharma Dr. Sakshi Angi	168
Ghorai an Jana	99	30.	Ambedkar's Vision of 'Dalit-Bahujan-Nationalism	Dr. Badal Sarkar	172
		31.	The Making of EBC in Bihar : From Karpoori to Nitish	Dr. Nagendra Prasad Verma	177
it Ahuja Sharma	102	32.	A CRITICAL REVIEW OF CONTENT AND PRESENTATION OF DNA PROGRAMME ON ZEE NEWS : AN EMPIRICAL STUDY	Adarsh Kumar	181
rs. Nidhi k Kadam	107	33.	FOREIGN COMMERCIAL BORROWING IN INDIA AND ITS DRIVERS	Mr. Ramakant Shukla	186
ıl Pandey	114	34.	POLITICS OF SOCIAL JUSTICE IN POST-MANDAL BIHAR	Dr. Md. Khaliqur Rahman	198
Dr. Rajni	118	35.	VOICE ASSISTANT : A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW	Prof. Pooja Darda Dr. R. M. Chitnis	202
		36.	CHANGING CONTOURS OF RIGHT TO PRIVACY IN INDIA	Dr. Sheetal Prasad Meena	208
hit Kumar ay Sharma ıil Bhadula	124				
Jeha Bharti ına Sharma	129				
ımika Sinha	14				
ımmad Saqib ohd. Rizwan ıma Siddiqui	14				
ımad Ganaie Anjali Mehra Jinny Sharma	15				

Head
Faculty of Law
J.N.Vyas University
Jodhpur

GOVT. OF INDIA RNI NO.: UPBIL/2015/62096

UGC Approved Care Listed Journal

ISSN
2229-3620

PPS

SHODH SANCHAR
Bulletin

An International
Multidisciplinary
Quarterly Bilingual
Peer Reviewed
Refereed
Research Journal

3.4.5/19
SPM

Vol. 10

Issue 40

October to December 2020

Dean & Head
Faculty of Law
J.N.Vyas University
Jodhpur

Editor in Chief
Dr. Vinay Kumar Sharma
D. Litt. - Gold Medalist

sanchar
Educational & Research Foundation

UGC APPROVED
CARE LISTED JOURNAL
GOVT. OF INDIA RNI NO. - UPBIL/2015/62096

ISSN No. 2229-3620

PPS

SHODH SANCHAR Bulletin

AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY QUARTERLY BILINGUAL PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

• Vol. 10 • Issue 40 • October - December, 2020

EDITORIAL BOARD

Prof. Arun Kumar Bhagat
Mahatma Gandhi Central University, Motihari (Bihar)

Prof. Santosh Kumar Shukla
Jawahar Lal Nehru University, New Delhi

Prof. Karuna Shankar Upadhyay
Mumbai University, Mumbai

Prof. Abdul Alim
Aligarh Muslim University, Aligarh

Prof. Padam Kant
University of Lucknow

Prof. Sheela Mishra
Usmania University, Hyderabad

Prof. Shraddha Singh
Banaras Hindu University

Prof. Pawan Sharma
Meerut University, Meerut

Prof. Hemraj Sundar
Mahatma Gandhi Sansthan, Moka, Mauritius

Prof. Susheel Kumar Sharma
Mizoram University, Mizoram

Prof. Arbind Kumar Jha
BBA Central University, Lucknow

Prof. Nagendra Ambedkar Sole
Central University of Rajasthan

EDITOR IN CHIEF

Dr. Vinay Kumar Sharma
Chairman
Sanchar Educational & Research Foundation, Lucknow

PUBLISHED BY

sanchar
Educational & Research Foundation

Dean & Head
Faculty of Law
J.N.Vyas University
Jodhpur

26.	AN EMPIRICAL RESEARCH ON CUSTOMER SATISFACTION TOWARDS LIC OF INDIA	Vaibhav Krishna Mishra Dr. Priyanka Rai	128
27.	आदिवासी महिला सशक्तिकरण में आदिवासी विकास विभाग का योगदान	निलेश दे. हलामी डॉ. राजविलास कारमोरे	134
28.	महिला सशक्तिकरण की दशा व दिशा	डॉ. के. एल. टाण्डेकर डॉ. (श्रीमती) आशा चौधरी डॉ. (श्रीमती) ई. व्ही. रेवती	139
29.	भारत में समान कार्य के लिए समान वेतन एक संवैधानिक एवं विधिक अध्ययन	डॉ. शीतल प्रसाद मीना	143
30.	प्रौद्योगिकी एकीकृत अध्यापक शिक्षा : समस्याएं एवं संभावनाएं	डॉ० एस डी सिंह 'परिहार' डॉ० शमीम अहमद	147

Dean & Head
Faculty of Law
J.N.Vyas University
Jodhpur

GOVT. OF INDIA- RNI NO. UPBIL/2014/56766
UGC Approved Care Listed Journal
ISSN 2348-2397

Shodh Sarita

An International Multidisciplinary Quarterly
Bilingual Peer Reviewed Refereed Research Journal

• Vol. 7 • Issue 28 • October to December 2020

3-4-5/10
SPM

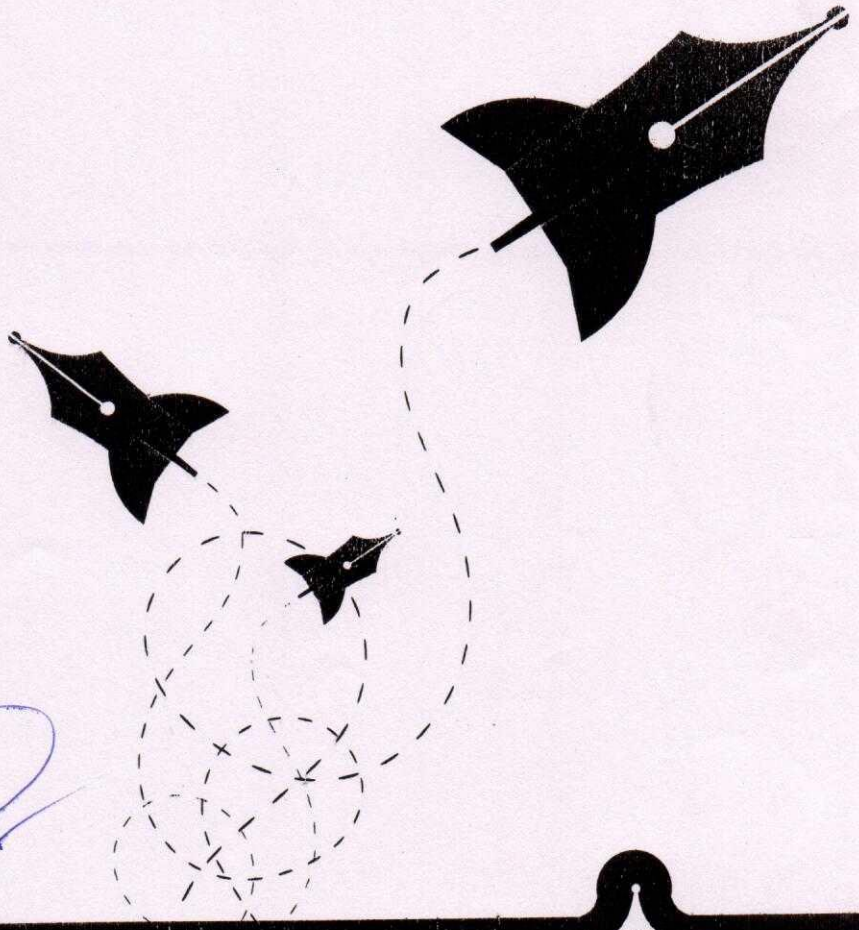

Dean & Head
Faculty of Law
J.N.Vyas University
Jodhpur

Editor in Chief
Dr. Vinay Kumar Sharma
D. Litt. - Gold Medalist

sanchar
Educational & Research Foundation

GOVT. OF INDIA- RNI NO. UPBIL/2014/56766 ISSN No. 2348-2397
UGC Approved Care Listed Journal

UUS

Shodh Sarita

AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY QUARTERLY BILINGUAL PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

• Vol. 7 • Issue 28 • October - December, 2020

EDITORIAL BOARD

Prof. Surya Prasad Dixit
University of Lucknow, Lucknow

Prof. Parmeshwari Sharma
University of Jammu, Jamnu

Prof. Kumud Sharma
Delhi University, Delhi

Prof. Ram Prasad Bhatt
Hamburg University, Germany

Prof. Sudheer Pratap singh
Jawahar Lal Nehru University, New Delhi

Prof. Girish Pant
Jamia Millia Islamia University, New Delhi

Prof. S. Chelliah
Madurai Kamraj University, Madurai

Prof. Ajay Kumar Bhatt
Amity University, Haryana

Prof. Pavitar Parkash Singh
Lovely Professional Universiy, Punjab

Prof. M.P. Sharma
Jamia Millia Islamia University, New Delhi

EDITOR IN CHIEF

Dr. Vinay Kumar Sharma
Chairman
Sanchar Educational & Research Foundation, Lucknow

Dean & Head
Faculty of Law
J.N.Vyas University
Jodhpur

PUBLISHED BY

sanchar
Educational & Research Foundation

27.	IMPACT OF RISK MANAGEMENT DECISION MAKING IN MICRO ENTERPRISES	Mr. Pulkit Kumar Dr. Priyanka Rai	151
28.	साहित्य मूल्यांकन की चुनौतियाँ : अमृतराय जी का दृष्टिकोण	प्रा. डॉ. विनायक य. खरटमल	157
29.	जीवन के जटिल यथार्थ की अनूठी गाथा : दुक्खम सुक्खम	प्रा. डॉ. सौ. सविता शिवलिंग मेनकुदळे	160
30.	बदलते भारतीय परिदृश्य में महानगरीय जीवन के समक्ष की नई चुन्नौत्तियाँ ('रास्तों पर भटकते हुए' उपन्यास के विशेष संदर्भ में)	डॉ. संदीप जोतिराम किर्दत	163
31.	डॉ. भीमराव अम्बेडकर का महिला सशक्तिकरण में योगदान	डॉ. शीतल प्रसाद मीना	168
32.	उच्च शिक्षा एवं शैक्षिक तकनीकी : भारतीय समाज में समावेशी परिवेश	डॉ० शमीम अहमद डॉ० एस डी सिंह 'परिहार'	171

Dean & Head
Faculty of Law
J.N.Vyas University
Jodhpur

ISSN No. (E) 2455 - 0817
ISSN No. (P) 2394 - 0344

RNI : UPBIL/2016/67980

VOL-4* ISSUE-12* March- 2020
Monthly / Bi-lingual

Multi-disciplinary International Journal

Remarking
An Analisation

Peer Reviewed / Refereed Journal

UGC S.NO. 40827
UGC approved listed
Till 14 June 2019

3.4.5 /11
D.S.

Dean & Head
Faculty of Law
J.N.Vyas University
Jodhpur

Impact Factor (2015)
GIF = 0.543

Impact Factor (2018)
IIJIF = 6.134

Indexed-with
Google scholar

Impact Factor (2018)
SJIF = 6.11

P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-4* ISSUE-12* March- 2020
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

Contents

S. No.	Particulars	Subject	Page No.	
			From	To
1.	**DSC and TGA on Diffently Fired Cadmium Oxide** Krishan Chandra Verma, Mahoba, Uttar Pradesh, India	Physics	E-01	E-03
2.	**Trends of Population Growth in Lakhimpur City: A Geographical Study** Karanjit Singh, Faizabad,U.P.,India	Geography	E-04	E-08
3.	**Value Degradation in Contemporary World and the Role of Teacher to Sustain and Disseminate the Human Values in Educational Institutions in 21st Century** Sushant Kumar Nayak, Arunachal Pradesh, India	Education	E-09	E-11
4.	**Religion and Literature: A Broad Perspective** Kavita Singh, Faizabad, Uttar Pradesh, India	English	E-12	E-13
5.	**The Study of the Effectiveness of the Inquiry-Based Learning Method in Chemistry Teaching Learning Process** Jogendra Singh & Vibha Kaushik, Jaipur, Rajasthan, India	Education	E-14	E-17
6.	**Natural Pollinators and Pollen Load Carried Out By Them In *Allium cepa L. (Alliaceae)*** A. S. Dahat, Arvi, Wardha, (M.S.) India	Botany	E-18	E-22
7.	**Land Use Land Cover Changes in Longai Reserve Forest of Karimganj District (Assam) from 1988 to 2010 (A Geospatial Approach)** Anup Dey, Karimganj, Assam, India	Zoology	E-23	E-27
8.	**Astronomy and Astrophysics in India during 1994 - 2015: Analysis of Geographically Distribution of Publications from Astrophysical Data System** Vijay Kumar Rai, Pune & Jiji Cyriac, Nagpur, Maharashtra, India	Astronomy & Astrophysics	E-28	E-37
9.	**Various Forms of Cybercrime against Women in India** Neeti Pandey, Gwalior, Madhya Pradesh, India	Law	E-38	E-39
10.	**An Analytical Study on Growth of Tourism Industry (With Special Reference to Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir)** Manohar Das Somani & Mohmmad Idrees, Indore, Madhya Pradesh, India	Commerce	E-40	E-45
11.	**Democratic Decentralisation In India With Special Reference To Centre-State Relations: An Overview** Dalpat Singh, Jodhpur, Rajasthan, India	Law	E-46	E-51
12.	**Appraisal of Dropout Children in Primary Schools: A Case Study of India** Surender Kumar, Hisar & Karamvir, Kurukshetra, Haryana, India	Geography	E-52	E-55
13.	**Emotional Intelligence and Achievement Motivation in High Schools Students** Jadav Taufik H. & Jogsan Y.A., Rajkot, Gujarat, India	Psychology	E-56	E-59

Dean & Head
Faculty of Law
J.N.Vyas University
Jodhpur

P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-4* ISSUE-12* March- 2020
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

Democratic Decentralisation in India with Special Reference to Centre-State Relations: An Overview

Paper Submission: 10/03/2020, Date of Acceptance: 27/03/2020, Date of Publication: 28/03/2020

Dalpat Singh
Assistant Professor,
Faculity of Law
Jai Narain Vyas University,
Jodhpur, Rajasthan, India

Abstract

Decentralization is a word that has been used by different people to mean a good many different things. In any case, what do we find by and by? Investigations with nearby government that end in confusion and insolvency; Decentralized structures of organization that serve just as an increasingly viable apparatus for unifying force; Regional and district committees in which government authorities settle on choices while neighborhood delegates stay quiet; Gram Sabhas where the neighborhood individuals partake yet have no assets to dispense. Decentralization helps in recognizing the requirements and inclinations of the individuals through their immediate contribution in plan detailing and usage. It engages the weaker sections and to some extent abolishes elite domination. In India, the Panchayati Raj system is recognized as a major means of decentralization through which democracy becomes truly representative and accountable. The Indian states were acting as federations at only two levels - the Union and the State. The 73rd Amendment reinforces the decentralization procedure in India and enables nearby bodies from states. The current paper considers the procedure of decentralization in India and the significant spotlight is on the 73rd Amendment, which manages district, sub-district and rural level institutions in rural zones.

Keywords: Decentralization, Panchayat, Government, 73rd Amendment, Political, Administrative And Fiscal Decentralization.

Introduction

Decentralization is a procedure of moving capacity to privately choose neighborhood governments. Transferring power means providing greater political authority to local governments (e.g., calling local elections or establishing participatory processes), increasing financial resources (e.g., transfers or through greater tax authority) and provide more administrative responsibilities. With enthusiasm for, and experiments, decentralization has swept the world throughout the most recent four decades. Hypothesis firmly contends that decentralization should expand resident voice and investment in the political procedure, and so the government should be made more sensitive and accountable to governance. These estimates have led to large-scale policy responses around the world, with estimates that 80–100 percent of the world's nations have tried different things with some sort of decentralization reform.[1]

Decentralization is a widely used concept, and is firmly connected with democracy, development and good governance. Several research findings clearly demonstrate that decentralization provides an institutional mechanism through which citizens at various levels can sort out themselves and take an interest in decision-making processes.

Local government is a type of a decentralized framework that is impacted by the exchange of power or duty from more significant levels of government to decision-making, management, or allocation of resources to its subordinate units. The job of nearby government changes starting with one nation then onto the next, but local government has a role in every democratic society. In most South Asian countries, rural authorities are characterized by a weak institutional capacity to deliver public services and promote local development.

Since the early 1980s, decentralization has re-emerged as an important political and financial objective in most developing nations. As indicated by an ongoing World Bank study, everything except 75 of the 75

Dean & Head
Faculty of Law
J.N.Vyas University
Jodhpur

ISSN No. (E) 2455 - 0817
ISSN No. (P) 2394 - 0344
RNI : UPBIL/2016/67980
VOL-3* ISSUE-11* February 2019
Monthly / Bi-lingual

Multi-disciplinary International Journal

Remarking
An Analisation

Peer Reviewed / Refereed Journal

Dean & Head
Faculty of Law
J.N.Vyas University
Jodhpur

Impact Factor
GIF = 0.543
Impact Factor
IIJIF = 6.134
Indexed-with
Google scholar
Impact Factor
SJIF = 5.879

3·45/12
05

APH PUBLISHING CORPORATION

4435-36/7 ANSARI ROAD
DARYAGANJ, NEW DELHI-110 002
Tel.:011-23274050/9810121903/9810136903/9818581487
E-Mail:aphbooks@gmail.com
(Publishers of Educational Journals and Books for last 45 years)

Dean & Head
Faculty of Law
J.N.Vyas University
Jodhpur

CERTIFICATE OF APPRECIATION

This certificate is awarded to Dalpat Singh
Environmental Crisis & Constitutional Enviro-Vision in India.
for contributing their Article/Research Paper in our Journal EDU CARE
ISSN 2319-5282 Volume No IX Issue Number 7 for month/year
Jan-Dec 2020

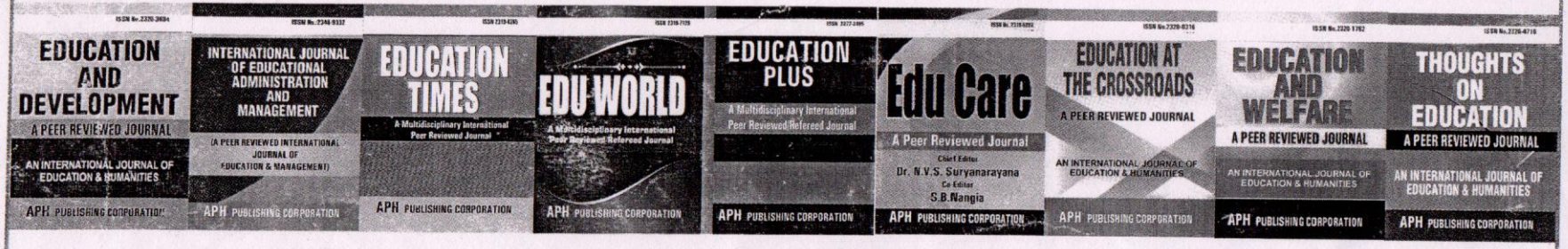

Place of Issue-New Delhi

APH PUBLISHING CORPORATION
4435-36/7, Ansari Road, Darya Ganj,
New Delhi-110002

Authorized Signatory
APH PUBLISHING CORPORATION
NEW DELHI

ISSN 2350-0603

Nehru Memorial Law College
HANUMANGARH

Bhatner
Socio-Legal Journal
A Peer Reviewed Refreed Journal

Vol. 6 Annual 2020

3.4.5 | 13
D.S

Dean & Head
Faculty of Law
J.N.Vyas University
Jodhpur

15. **Asylum/Refugee Protection Structure Infusing in to Maldivian: A Legal Analysis** 9
Dr. Mohammad Rauf & Fathimath Iuthisam Abdulla Ibrahim

16. **Rampant Corruption in Police System: Need for Legal and Judicial Reforms for the Protection of Constitutional Rights in India** 98
Dr. Saurabh Garg

17. **Honour Crimes against Women: International Human Rights Law Perspectives** 104
Dr. Vinod Kumar

18. **Female Foeticide and the Question Mark on Surrogacy in India: An Analytical Study** 115
Dr. Brajesh Kumar Agarwal

19. **Misleading Advertisement and Consumer Protection Laws in India: A Conceptual Analysis** 122
Dr. Mohammad Azvar Khan

20. **Admissibility of Electronic Evidence without Certificate under Section 65B of Evidence Act, 1872** 134
Dr. Arshad Hussain & Dr. Shoaib Mohammad

21. **Human Rights of Prisoners: A Study in Context of State of Punjab** ... 137
Dr. Divya Sharma & Karanjit Singh

22. **Right to Children's Education: A Social Legal Study with Reference to National Balbhawan, New Delhi** 143
Dr. Reshma Khatoon

23. **Honour Killing in India and the World: A Socio-Legal Analysis** ... 148
Suneel Kumar

24. **Attempt to Answer Dichotomy Vis-A-Vis Artificial Intelligence** 159
Karan Kataria & Mohit

25. **Role of Human Rights Commissions to Protect the Human Rights in India: Need of the Hour** 171
Dr. Dalpat Singh

26. **Democratic Governance and Public Policy Making: Examine the Ground Realities in India** 180
Dr. Surendra Singh & Dr. Rajesh Kumar

27. **Law on Maintenance to Wife and Children: A Brief Inquiry** 191
Shoyab Mohammad

28. **Undue Process of Police Encounters** 198
Dinesh Khoth & Manish Swami

29. **Protection from Pandemic of Covid -19 under Legal Perspective: A Critical Analysis** 203-209
Kapil Dev

30. **Police Reform in India** 210-217
Divakar Gahlot

31. **Questionable Role of Governor in India** 218-223
Pushpender

32. **Intersectionality of Child Marriage and Human Trafficking** 224-232
Manjula Raghav

33. **An Analysis of Dishonour of Cheques under the Negotiable Instruments Act, 1881** 233-238
Seema Modi

34. **Biomedical Waste Management System under Indian Legal Framework** 239-249
Farzin Naz & Jayanta Boruah

35. **Enforcement of Foreign Arbitral Award in India: Enforcement and Public Policy** 250-260
Christi Anna George

Dean & Head
Faculty of Law
J.N.Vyas University
Jodhpur

physical wron
guilty mind at
problematic b
though the ac
machines worl
the brain of its
a mind that ca
to a basic mac
mental ability
Criminal Law[2]
general doctrir
artificial intelli

The autor
of the defenda
harm caused o
the circumstan
knowledge and
predictability i
A user can't fc
cannot make th
or a representat

In Bountal
Germany was
incident took p
convolutions be
the latter being

Legal unce
case, a man driv
driving and lost
towards the surr
its AI brought t
AI of the vehicl
the car was bro
still unconsciou
of criminal acc

27 Michael Bohla
28 Associated Pre
(July 2, 201:
plant-in-germa

law and science during this regard shall not overpower instead they must cor
one another. The scientific advancement is additionally replacing humans v
conducting basic deciding tasks. Unlike criminal and privacy law, there's h
legal development within the world of employment laws from this attitude.
development should make the pace with scientific evolutions in this regard.

In light of all the factors discussed, contemporary situation analyzed an
of the hour realized, it's probably fair to mention that AI is currently durir
of a cocoon. during a tutorial legal research, AI remains almost "terra ir
The legal framework shall initiate the acceptance of AI within the legal
International Law and several countries have been a catalyst as discusse
antitrust legislation they can serve as the foundation to accelerate its acce
divulge its path to a more ethical and practical framework of law.

Dean & Head
Faculty of Law
J.N.Vyas University
Jodhpur

ıle of Human Rights Commissions to Protect the Human Rights in India: Need of the Hour

Dr. Dalpat Singh[1]

duction

ian Rights Commission is an expression of India's concern for the protection
ıotion of human rights. It is a unique expert body, which is created under the
n of Human Rights Act, 1993, for examining and investigating the complaints
ɔ violations of human rights, as also the negligence on the part of any public
ı preventing such violations. Subsequently, the PHRA, 1993. has amended
ır 2006 for effective A implementation of human rights[2]. The proposal for a
ion as originally contained in a Huiran Rights Commission Bill which was
d in the Lok Sabha on 14th May, 1993. When the same was considered by the
ıtary Standing Committee on Home Affairs, it was extensively criticised with
powers, functions and manner of functioning of the proposed Commission.

truggle for protection and promotion of human rights is long and arduous. It
nt that we constantly remain engaged in devising structures and institutions,
make us all more sensitive and responsive towards protection and promotion
rights. It is to be noted that the wide comprehension o human rights indicates
diciary alone is not equipped to perform the entire task of promotion and
of human rights. There is a need of a similar institution to complement the
ɔy monitoring the functioning of the institutions of the State, which most
esponsible for violation and neglect in prev.ntion of violation of human
: National Human Rights Commission is an instil ution acts a a catalyst to
ıe quality of governance, on which depends the state of himan rights in a

ia, the Human Rights Commissions can play a vital role in influencing
making and sometimes even policy initiations, facilitating protection and
of human rights, such institutions provide an excellent mechanism for
ıblic opinion and strong alliances and partnerships with non-governmental

t Professor, Faculty of Law , J.N.V.U. Jodhpur
2006, Received the assent of the President on September. 13.2006 and published in the
of India. Extra,. Part II, Section 1, dated 141 I September, 2006. pp. Ito 7. S. No. 50
ehgal .B.P. 'Human Rights in India: Problems and Perspectives' Deep & Deep Publi

ISSN : 2456-4397 Vol.-6* Issue-2* May-2021 Bilingual / Monthly
RNI : UPBIL/2016/68067

Multi-disciplinary Peer Reviewed/Refereed International Research Journal

Anthology The Research

Publisher : Social Research Foundation, Kanpur (SRF International)

Impact Factor
SJIF = 6.018
IIJIF = 4.02

Indexed-with Google scholar

3.4.5/14
DS.

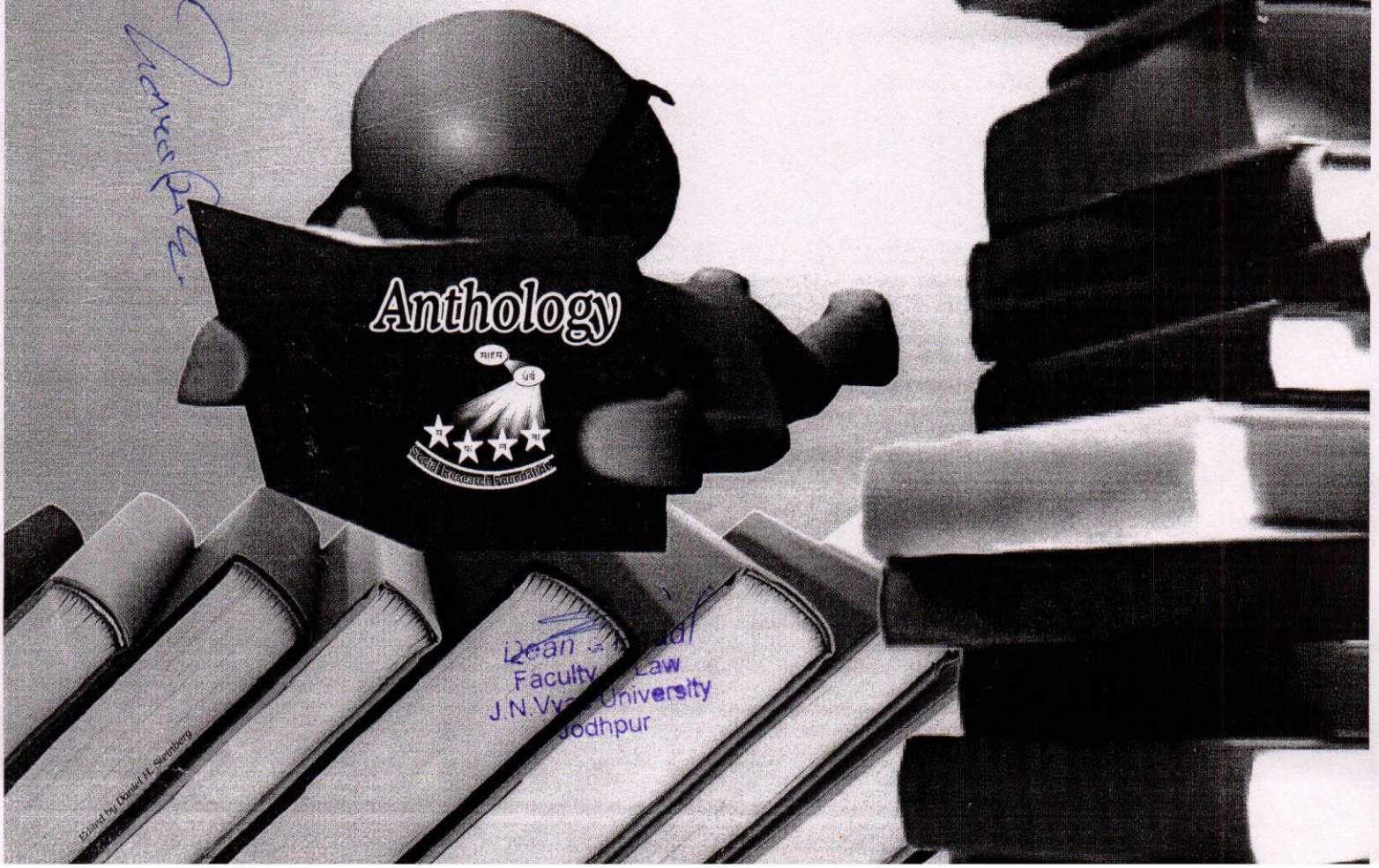

Dean ...
Faculty ... Law
J.N.V... University
Jodhpur

ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-6* Issue-2* May- 2021
Anthology : The Research

Contents (English)

S. No.	Particulars	Subject	Page No.	
			From	To
1.	**Water Resource Management** Anita Rathore, Udaipur, Rajasthan, India	Geography	E-01	E-03
2.	**Phytochemical studies on Ethanolic Extract (Stem, Leaf and Fruit) of Indian Traditional Medicinal Climber "*Cocculus Hirsutus*"** Rajendra Prasad, Bundi, Rajasthan, India	Botany	E-04	E-10
3.	**A Study on Impact of Goods and Services Tax on different Sectors of Economy** Rajeshwar Tiwari & Ved Prakash Jaiswal, Mirzapur, Uttar Pradesh, India	Food Processing & Modern Office Management	E-11	E-13
4.	**Exploration of the Cultural Aspects of Hindi Food Expressions Concerning Hindi Foreign Language Education** Dwivedi Anand Prakash Sharma, Delhi, India	Hindi	E-14	E-22
5.	**Environment and Media** Meenakshi Sharma, Moradabad & Manmeet Kaur Bareilly, U P, India	Political Science	E-23	E-26
6.	**Gandhian Ideology as a Reflection of Light** Mohammad Arif, Varanasi, Uttar Pradesh, India	Political Science	E-27	E-32
7.	**Empowerment of Indian Women: An Analysis of Dr. B.R. Ambedkar's Contribution** Sujata Mainwal, Meerut, Uttar Pradesh, India	Sociology	E-33	E-36
8.	**Human Rights of Disadvantaged Groups : Corruption and Good Governance** Dalpat Singh, Jodhpur, Rajasthan, India	Law	E-37	E-42
9.	**Society, Patriarchy and Women: An overview of the gender scenario in India** Anupama Saha, Sirohi & Anuradha Srivastava, Pali, Rajasthan, India	History	E-43	E-49
10.	**New Trends and Themes in the Poetry of 20th and 21st Century Indo-Anglian Women Poets** Arvind Kumar, Khatauli, Uttar Pradesh, India	English	E-50	E-54
11.	**An overview of the Eco-environmental approaches in Social and Cultural Anthropology** Vinod Ranjan & Seema Mamta Minz, Jharkhand, India	Anthropology	E-55	E-60
12.	**Organisational Climate: Its Impact on Teacher Commitment** Abhilasha Jaiswal, Varanasi, Uttar Pradesh, India	Education	E-61	E-64

Dean & Head
Faculty of Law
University

ISSN: 2456–4397 RNI No.UPBIL/2016/68067 Vol-6* Issue-2* May- 2021
Anthology : The Research

Human Rights of Disadvantaged Groups : Corruption and Good Governance

Paper Submission: 02/05/2021, Date of Acceptance: 15/05/2021, Date of Publication: 25/05/2021

Dalpat Singh
Assistant Professor,
Faculty. of Law,
Jai Narain Vyas University,
Jodhpur, Rajasthan, India

Abstract

Global human rights law will offer qualities, standards and rules that modify a standard meaning of majority rule government. This paper inspects the significant segments of minorities, helpless and disadvantaged groups: Values, standards and standards in popular government get from global human rights law.

It regrets that corruption undermines the enjoyment of human rights and, at the same time, employs human rights as a standard framework to condemn and combat corruption. But the human rights-based approach has been criticized as vague and over-reaching. In addressing this controversy, this article attempts to examine more closely the legal quality of the fictitious 'link' between corruption and human rights. Corruption can contribute to closing the implementation gap of international anti-corruption tools not only as human rights issue but also as a potential human rights violation and usefully complement the dominant criminal law-based approach.

Keywords: Human Rights, Disadvantaged Groups, Corruption, Good Governance.

Introduction

As a concept, human rights have been constantly developing all through human history. They have been complicatedly attached to laws, customs and religions for quite a long time. Their standards change over the long haul as per human necessities and interests. Any conversation about human rights should recognize philosophical, political, and legal records. The way of thinking of human rights deciphers the rationale of human rights while governmental issues reveal to us which group of human rights needs quick thought, which group of human rights should we identify and how might we evaluate the conduct of other human rights. Notwithstanding, the law of human rights manages an itemized depiction of globally concurred qualities, standards or decisions that oversee the direction of states towards their residents and non-residents.

But philosophical, political and legal ways to deal with human rights won't be talked about exhaustively for the basic explanation that it is past the extent of work. All things being equal, the most fundamental components of the concept of human rights that give a birds-eye perspective on the above approaches will be made. The reason for doing this is to make an association between human rights and defilement. With this view, the accompanying sections investigate and examine the definition (if any), premise, nature and classifications of human rights.

Objective of the Study

1. To work for ensuring that basic human rights are respected everywhere.
2. To restrict cooperation with governing regimes that violates human right.
3. To actively engage with the Government of India to promote human rights education.
4. To support disadvantaged groups for protection of their rights.
5. To aware about the human rights of disadvantaged groups.
6. To discuss about the causes and impact of corruption on human rights.
7. To presurise to the government to remove corruption on human rights and makes arrangements for good governance.

Definition of Human Rights

In the worldwide field, where assorted societies are included, where positivist bases are unsteady, and where execution components are delicate, the meaning of human rights is significant. Since one understands

Dean & Head
Faculty of Law
J.N.Vyas University
Jodhpur